which will also satisfy the coconut farmers a little bit. Actually, the coconut farmers are demanding ₹ 100 per kilo. If ₹ 100 is not given, at least, it must be made ₹ 75/- per kilo, and, it must be procured by the Government. This is the position of today. Actually, the price of DAP, the price of potash as also the price of NPK complex fertilizer has gone up. So, the Government must be liberal in giving the Minimum Support Price for all the farm produce. Thank you.

MESSAGES FROM LOK SABHA — *Contd.*

The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016

SECRETARY-GENERAL: I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th July, 2016."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION — *Contd.*

Situation arising out of price rise in the country

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now, Shri Harivansh.

श्री हरिवंश (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मूल्य वृद्धि पर हो रही अल्पकालिक चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। मेरा आग्रह है कि यह सरकार मान ले कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो बुनियादी चुनौतियां है, इनके हल करने का सामर्थ्य इस सत्ता पक्ष के पास नहीं है, इसका समाधान यह सरकार नहीं ढूंढ़ पाएगी। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि यह सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियां हल कर पाएगी, लेकिन देश में सत्ता पक्ष के इस आश्वासन को कि "अच्छे दिन आएंगे" पर लोगों ने भरोसा किया। आज दो वर्ष निकल गए, सिर्फ तीन वर्ष ही बचे हैं। हमारी तरफ एक कहावत है कि "पूत के पांव पालने में।" यानी इन्होंने दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी के चैलेंजेज़ को ये सिर्फ बातों से हल कर सकते हैं, इनमें सामर्थ्य और क्षमता नहीं है कि चीजों को ये नियंत्रित कर सकें। मैं यह क्यों कह रहा हूं, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन के मापदंड के लिए कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स (सी.पी.आई.) को प्रतीक मानते हैं। इससे खाने-पीने की चीजों का भाव पता चलता है। अप्रैल, 2016 से जून, 2016 के बीच सी.पी.आई. इन्फ्लेशन इंडेक्स 4.8 परसेंट से बढ़कर 5.8 हो गया है। इतना ही नहीं, मैं सरकार के आंकड़े बतलाना चाहूंगा। यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सौजन्य से है

[श्री हरिवंश]

कि 7 से 14 जुलाई के 2016 के बीच चीजों के भाव क्या थे। गोरखपुर में टमाटर 65 रुपए प्रति किलो, आइज़ॉल में आलू 35 रुपए प्रति किलो, प्याज 40 रुपए प्रति किलो, भटिंडा में मूंगफली तेल 171 रुपए प्रति किलो और तुअर दाल 170 रुपए प्रति किलो, पणजी में उड़द की दाल 190 रुपए प्रति किलो, सरसों का तेल 179 रुपए प्रति किलो, उदयपुर में मसूर दाल 110 रुपए प्रति किलो, पोर्ट ब्लेयर में चीनी 50 रुपए प्रति किलो, मैसूर में चावल 45 रुपए प्रति किलो। ये सारे आंकड़े हमारे नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि आलू, प्याज, टमाटर के भाव कैसे बढ़े। सारे उपायों के बाद चीनी कैसे अनियंत्रित हो रही है, दालों के भाव कैसे अनियंत्रित हो रहे हैं।

मैं दो खबरों का उल्लेख करना चाहूंगा कि जो देश के सबसे बड़े अखबारों में सुर्खियों के रूप में आई। 15 जुलाई, 2016 की खबर में "थोक महंगाई भी 20 माह की ऊंचाई पर पहुंची"। 14 जून, 2016 की खबर में "रिटेल महंगाई ने छुआ 21 माह का उच्चतम स्तर"। अभी हम लोगों ने सत्ता पक्ष से बहुत सारे आंकड़े सुने। मैं कुछ आंकड़े देकर आपको बताना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई बीते 22 महीने के उच्चतम स्तर पर 5.77 फीसदी पहुंच गई है। दालों में 26.86 फीसदी कीमत वृद्धि, चीनी में 16.79 फीसदी वृद्धि। सब्जियां - 14.74 परसेंट कीमत वृद्धि, मसाले - 8.61 प्रतिशत कीमत वृद्धि, मांस-मछली - 6.60 प्रतिशत कीमत वृद्धि, दो साल में अरहर के दाम में दोगुनी वृद्धि और उड़द के दाम में 120 फीसदी वृद्धि। यह स्थिति सरकार के द्वारा दिए गए आँकड़ों की है और वास्तविक स्थिति इससे और अधिक गम्भीर है, जबकि यह सरकार लगातार बात करती है कि हम गांवों के लिए और गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि शहरों की तुलना में गांवों में महंगाई बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। मैंने उन चीज़ों की भाव-वृद्धि की याद दिलाई, जो रोज़ की थाली के हिस्से हैं। यह सरकार लोगों से रोज़ खाने की थाली तो छीन ही रही है, ऊपर से इस महंगाई की मार सबसे अधिक उन गांवों पर है, जो सबसे अधिक गरीब हैं। गांवों में रिटेल महंगाई की दर 6.45 फीसदी से बढ़कर 7.24 फीसदी हो गई है। अब मैं और तथ्य न रखकर यह कहना चाहूँगा कि जब महंगाई का ग्राफ नीचे होता है तो श्रेय केंद्र सरकार लेती है, पर कीमतें बढ़ने पर दोष डालने के लिए राज्यों की बात करने लगती है, जबकि यह शुद्ध रूप से अर्थ-नीति से जुड़ा हुआ मामला है और अर्थ-नीति केंद्र सरकार के हाथ में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने कुछ सवाल रखना चाहूँगा। ऐसा क्यों होता है कि फसलों और सब्जियों के भाव बढ़ते हैं, पर किसानों को इस भाव-वृद्धि का लाभ नहीं मिलता? क्यों बीच के लोग इसका लाभ उठाते हैं? केंद्र सरकार की अर्थ-नीतियां उनके सामने क्यों असहाय एवं लाचार दिखती हैं? टेक्नोलॉजी और चुस्त गवर्नेंस के दौर में सरकार अब तक इसका क्या समाधान निकाल पाई है? मैं याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के अपने चुनाव घोषणा-पत्र में किसानों को उनकी उपज का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा किया था। उस वायदे का क्या हुआ? तीसरी बात, इस सरकार में किसानों के लिए कितना दर्द है, उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। इस सरकार ने किसानों के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 60 रुपये प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि की। यह शुद्ध रूप से किसानों के साथ घोर अन्याय है। किसानों के वोट लेने के लिए चुनाव में कैसे उनमें भ्रम पैदा किया गया, इस स्थिति को आज देश देख और समझ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा-पत्र में महंगाई पर नियंत्रण

के लिए "मूल्य स्थिरीकरण कोष" बनाने की बात कही थी। इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, यह मैं सरकार से जानना चाहूंगा।

महोदय, अगली बात यह है कि फाइनेंस बिल, 2016 इस संसद से 2016 में ही पास हुआ। इसका काम मॉनिटरी पॉलिसी को नियंत्रित करने के लिए कमिटी बनाना था। इसका मूल काम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और रेपो रेट तय करना है। इसका गठन जून, 2016 में हो पाया है। इसने अभी तक महंगाई नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया या क्या कदम उठाए, इसकी सूचना नहीं है। मैं आगे यह कहना चाहूँगा कि महंगाई पर जिन्हें दर्द है, उन्होंने सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर भव्य आयोजन किए। अगर सचमुच महंगाई से दर्द था, सूखे में जो दो वर्ष गुजरे और किसानों की आत्महत्याएँ बढ़ीं, तो आपको सरकार ईवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलानी चाहिए थी, बल्कि उस ईवेंट मैनेजमेंट का पैसा किसानों के बीच लगाना चाहिए था, गरीब इलाकों में खर्च करना चाहिए था। ...**(समय की घंटी)**... दूसरी ओर यह हालत है कि सरकार के आँकड़े बताते हैं कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब है। इस बीच, आपने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू कर दीं, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आप समृद्धि का नखलिस्तान खड़ा कर रहे हैं, पर इसके बाहर बहुसंख्यक गरीब हाशिये पर हैं। वंचित आदिवासी और अल्पसंख्यक की आमदनी नहीं बढ़ रही है।

अंत में, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से सामाजिक विषमता बढ़ रही है, गरीबों की हालत दयनीय है और महंगाई अनियंत्रित है। इस सामाजिक तनाव की स्थिति में महंगाई आग में घी का काम कर रही है। इस आग की आंच अभी सरकार तक पहुँच रही है। इस महंगाई की आंच में व्यवस्थाएँ-सरकारें भस्म होती रही हैं, इस बात को यह सरकार जितनी जल्दी समझ ले, उसके हित में है, देशहित में है और लोकहित में है, धन्यवाद।

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा): महोदय, हम हर बार, हर सेशन में महंगाई के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन महंगाई कभी कम नहीं होती या महंगाई की दर कभी कम नहीं होती। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महंगाई को लेकर हम जब तक एक स्थायी पॉलिसी नहीं बनाएँगे, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। महोदय, महंगाई दर को लेकर इस सरकार ने दो साल पहले काफी वायदे किए थे और महंगाई घटाने की बात कही थी, लेकिन महंगाई घटने की बजाय बढ़ गई है। केवल consumer goods ही नहीं, साग-सब्जी, vegetables, इन सब आइटम्स के दामों में difference आ गया है। महोदय, मैं चार साल से दिल्ली में हूं। यहां dairy products के दामों में भी काफी वृद्धि हो गयी है। एक समय था, जब weekly हमारा राशन चार-पांच सौ रुपए में आता था और उसमें गुज़ारा हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में weekly 1,200 से लेकर 1,400 रुपए तक का राशन हमें खरीदना पड़ता है। दलहन की जो समस्या हमारे देश में है, वह हम सबको मालूम है। सरकार को अब सोचना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा दाल import करके हमारी मार्किट में पहुंचाए। हमारे जितने भी छोटे वर्ग के लोग हैं, चासी-मुलीया लोग हैं, वे per day 100 या 150 रुपए कमाते हैं। वे लोग कहां से दाल या सब्जी खरीदकर जी पाएंगे? महंगाई कम न होने का मुख्य कारण यह है कि जो फायदा हमारे consumer को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम में टैक्स नहीं घटाया गया है, जबकि international market में पहले वह per barrel 130 डॉलर था जो अब घटकर 47 डॉलर रह गया है। यह पहले इससे भी कम था, 30 डॉलर per barrel था। इससे हमारे common लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है।

[श्री दिलीप कुमार तिर्की]

महोदय, हमारी स्टेट ओडिशा ने एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से जितने भी राज्य हैं, उनमें सबसे पहला राज्य ओडिशा है, जिसने पेट्रोल पर टैक्स कम किया है। मेरे ख्याल से हमारे मुख्य मंत्री श्री नवीन पटनायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। West Bengal और अन्य भी कई ऐसे राज्य हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे विचार से आपको उनसे सीखना चाहिए।

आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जितने भी गरीब या lower income वाले लोग हैं या average income वाले लोग हैं, उनके पास proper दर पर सामान कैसे पहुंचाया जाए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now, Shri Ashok Siddharth, not here; Shri Praful Patel, not here; Shri K. T. S. Tulsi, not here. Now, Dr. Narendra Jadhav.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated): Sir, inflation is the most iniquitous form of taxation because it hurts the poor the most. The headline's say, CPI inflation rate year on year has turned to about 5.77 per cent in June, 2016, up from 4.83 per cent in March. The CPI inflation was mainly driven by food inflation, which registered an acceleration for the third successive month. Food and beverages sub-group recorded the largest price pressures year on year at 7.4 per cent driven by vegetables whose prices rose by 14.7 per cent month on month and also protein-rich items, sugar, spices and cereals.

Sir, I would like to talk about the five factors which are responsible for the recent spurt. The rise in retail inflation in the recent period is due to a larger than seasonal jump in food prices. Basically, what has happened, Sir, is that the demand-supply imbalance generated by shortages in domestic production induced by two consecutive years of deficient monsoon has led to a gradual edging of inflation. With production trailing demand in recent years, shortages of essential commodities have widened. For example, inflation in respect of pulses has remained very high because the production of pulses has fallen for the second consecutive year. The second factor responsible for the recent spurt is the leakages and inefficiencies in the food management system and inadequate supply chain management. These have also led to the price spiral. The MSP policy, which was highly skewed in favour of rice and wheat, has discouraged the other key items leading to shortfall in their production.

Thirdly, hoarding and speculative activities by the middlemen have created artificial scarcity in some commodities. The benefit of high prices paid by consumers does not flow back to primary producers, that is, farmers. But it is siphoned away by middlemen and speculators who enjoy a free run in an economy of shortages.

The fourth factor is that the infrastructure for post-harvest management of farm products to ensure proper storage and smooth supply to market is quite weak in our country. India, Sir, is world's largest producer of fruits and vegetables. But the shortage and transportation losses for several crops are estimated to be around 30-40 per cent. Unfortunately, there is no silver lining in sight. Although we say that satisfactory monsoon this year and a reasonable spatial and temporal distribution of rainfall along with various supply management measures should moderate the unanticipated flares in food inflation, nevertheless, I would like to warn this august House that there are several upside risks, particularly, there is an uncertainty over oil prices and there is the issue of implementation of the Seventh Central Pay Commission awards. The Reserve Bank Report on Monetary Policy in April, 2016 has shown that the direct impact on inflation, with the Seventh Central Pay Commission recommendations, is expected to be about 1.5 per cent and the indirect effect is going to be around 40 basis points or 0.4 per cent. This is very significant.

Sir, I would like to very briefly talk about seven remedial measures in quick succession. First one is that stringent measures are required, particularly, by the State Governments to crack down on speculative hoarding activities. Secondly, for monitoring of commodity derivatives trading, which may at times fuel a speculative spiral in prices, what is required to put in place appropriate regulations. Thirdly, improving food management policy, by proactively releasing the food stocks of essential items, plugging the leakages and ensuring their availability, that is to say, releasing additional stocks from Government warehouses for supplies to State Governments, is imperative. The Food Corporation of India could also undertake open market sales wherever feasible. At the same time, it is imperative to increase the off-take through existing Public Distribution System. Sir, this would keep in check the price pressure and also ensure more equitable distribution and food security.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Only bullet points, please.

DR. NARENDRA JADHAV: Yes, Sir. Quickly going forward, Sir, efficient market infrastructure, improved storage capacity and faster transportation from producers to customers are the vital areas that need greater attention. The transformation of agriculture has to be steered by raising productivity in agriculture by investing in efficient irrigation technology. It is equally important to gradually move away from the cereal-centric MSP policy towards other items with supportive policy framework and required infrastructure. Policy interventions are required to support sustainable growth in crop production and environmental protection through development of improved and diversified cultivation, eco-friendly and cost-effective pest management practices and efficient seed supply systems.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Okay, thank you.

DR. NARENDRA JADHAV: One final point, Sir. The rebalancing of the Government expenditure needs to be pursued by staying on the path of fiscal consolidation going forward.

Finally, Sir, a strong monsoon, continued with astute food management as well as steady expansion in supply capacity, especially, in services, could help offset these upward price pressures. Thank you very much.

श्री नीरज शेखरः उपसभाध्यक्ष महोदय, सिद्धार्थ अशोक जी आ गए हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): After this circle is completed, he will be called. ...(*Interruptions*)...

श्री नीरज शेखरः आप इनको बोलने का अवसर दे दीजिए। यह इनकी मेडन स्पीच है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): He will be called. ...(*Interruptions*)... He will be called. Please wait. ...(*Interruptions*)... He will be called. Shri Sanjay Raut; not present. Sardar Balwinder Singh Bhunder; not present. Shri D. Raja; not present. Shri R.S. Bharathi.

SHRI R. S. BHARATHI (Tamil Nadu): Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the issue of price rise. First and foremost, I would like to thank my beloved leader, Dr. Kalaignar, for reposing faith in me and electing me to the Council of States. I also acknowledge the leaders of the Dravidian movement, including our great Anna, who paved the path in this very House for someone like me.

Sir, through you, I would like to assure the people of Tamil Nadu that I will represent them to the best of my abilities and raise the voice of the State at every opportunity. Many of them have spoken about the causes of rising prices. Sir, I would like to say that in my opinion, the main reason for the price rise is the rise in prices of fuels, because agriculturalists depend upon fuel and common people depend upon gas for cooking. So, I would request the Central Government to pay special attention to bring down the cost of the fuels, which has caused great inconvenience to all sections of the people.

Sir, I would not take much time of the House. I would only like to make three points, and I would request the Government to give special consideration to these three points. Sir, I take this opportunity to suggest three easy measures for the Government of India to consider while tackling the price rise. Number one is, checking of hoarding; take swift action against those who indulge in large-scale hoarding of essential commodities. The Union Government needs to evolve a

dedicated multi-disciplinary agency to investigate, prosecute and prevent those who are hoarding food grains and vegetables for the sake of making windfall profits. I urge upon the Government to report to the Parliament, on the action taken in this regard, at least, in the next Session.

The second point is, to improve storage capacity. An RTI reply filed by the 'Times of India' has revealed that nearly 20,000 tonnes of food grains stored in the godowns of Food Corporation of India, were wasted from rotting in one year, *i.e.,* from 2014-15. In one year alone, 20,000 tonnes of food grains were wasted by the Food Corporation of India.

In this respect, I would also like to submit that 60 per cent of the children in India are going to bed hungry. At this stage, Sir, can this be accepted that 20,000 tonnes of food grains is being wasted, and at the same time, 60 per cent of our children go to bed hungry? This cannot be accepted, Sir. The Government has to show special attention towards the Food Corporation of India. At least, in future, we have to improve our food storage facilities and improve the supply-chain management, so that wastage is minimized.

Sir, last but not least, I would request the Central Government to expand the *Uzhavar Santhai Scheme*. In order to benefit the farmers and consumers equally and remove the menace of middlemen, from 2006 to 2011, my leader Dr. Kalaignar, who was the Chief Minister of Tamil Nadu, introduced a noble scheme known as *Uzahavar Santhai, i.e*, 'farmers' markets' across Tamil Nadu. This reduced the prices of essential commodities and provided good returns for the farming community as well. I urge upon the Government to introduce such farmers' markets in every district in the country. Sir, with these words, I conclude and thank you once again.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Now, Shri Pramod Tiwari.

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री रघुराम राजन कह रहे हैं। वे चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि कोई बताए, महंगाई कहां कम हुई है? महंगाई बढ़ी है। तो जब इनकी सरकार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम नहीं हो रही है, तो सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य था कि जब ये बोलते, तो यही कहते कि "हां महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम महंगाई कम करेंगे।" महोदय, मैं आप से इस सवाल को समझना चाहता हूं। सरकार के सामने जो लोग बैठे हैं, वे कह रहे हैं कि महंगाई दिख रही है, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष शुरू होता है, इनको महंगाई नहीं दिखती। मैं इनसे वह फार्मूला जानना चाहता हूं कि क्या बात है कि आपको महंगाई नहीं दिखती? महंगाई है, यह सब मानते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है, कहावत है कि सावन के महीने में अंधे को हरा, हरा ही दिखाई देता है। तो जब तक आप वहां बैठे हो, आपको महंगाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब जनता

[श्री प्रमोद तिवारी]

के बीच में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इस समय देश में दो ही समस्याएं हैं — एक आतंकवाद और दूसरी महंगाई और दोनों में आप फेल हो गए हो। आप महंगाई रोक नहीं पा रहे हो, यह सच्चाई है। हां, आंकड़े हैं, महंगाई 7.5 परसेंट तक पहुंच गयी। यहां पर महंगाई बढ़ जाती तो हम मान लेते कि महंगाई बढ़ गयी, लेकिन मेरा सीधा-सीधा सरकार पर आरोप है कि इस देश में जो महंगाई बढ़ी है, वह किसान ने, व्यापारी ने नहीं बढ़ायी है, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बढ़ाई हुई महंगाई है। आपने आते ही रेल भाड़ा 16 परसेंट बढ़ा दिया, तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? आप सब से पहले सर्विस टैक्स बढ़ा देते हो, जब सर्विस टैक्स लगाओगे तो जिस चीज की भी सर्विस होगी, उस पर टैक्स बढ़ गया तो महंगाई बढ़ गयी। मोदी जी 15 अगस्त को भाषण देते हैं और आप सर्विस टैक्स लगा देते हो। आप हर चीज पर टैक्स लगा देते हो, इसलिए पीठासीन अधिकारी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब इनका वश चले तो हर सांस पर आप टैक्स लगा दोगे। यही बाकी रह गया है, वरना आप हर चीज पर टैक्स लगा देते और आपके लगाए टैक्स से ही महंगाई बढ़ रही है।

आप आज बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों के रेट देख लीजिए। इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो? आज बाजार में क्रूड ऑइल का रेट 42.0 प्रति डॉलर है और आप बेच रहे हो, डीजल 54.33 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल रुपए 63.2 पर लीटर। तो यह महंगाई कौन बढ़ा रहा है? यूपीए की सरकार में 110-115-120 डॉलर प्रति बैरल पर खरीदकर, हमने 150-155 रुपए के हिसाब से और आप बेच रहे हो 42 डॉलर पर खरीदकर। तो सीधी सी बात है कि आप मुनाफाखोरी कर रहे हो, आप खुद जनता की जेब पर डाका डाल रहे हो। आप गुनाहगार हो कि सस्ता खरीदकर महंगा बेच रहे हो और आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। मेरा आप पर यह सीधा आरोप है, अगर हिम्मत है तो खड़े होकर कह दीजिगा कि हम कल से बाजार रेट पर बेचेंगे, तो शायद कुछ राहत मिल जाए।

महोदय, अभी बहन रजनी जी कह रही थीं कि, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। बहन जी को यह बात मालूम नहीं है कि जब देश महंगाई में जल रहा था, तो हमारे प्रधान मंत्री जी ड्रम बजाकर महंगाई कम कर रहे थे। शायद उनकी उस ताल से महंगाई कम हो जाए। ये किसी भी हालत में नीरो से कम नहीं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप घर में कभी पत्नी से पूछना कि दाल क्या भाव मिली? हमारे समय में दाल का भाव 75 रुपए था तो आप सड़क पर थे और 210 रुपए की दाल खरीदकर आप घर के अंदर बैठे हो? आप सोचिए कि आज क्या हालात हो गए हैं? हां, एक चीज जरूर है कि आप बातें बहुत लंबी-लंबी करते हो, लेकिन आपका उनसे कुछ रिश्ता रहा है। मुर्गी सस्ती, दाल महंगी, अंडा सस्ता, आलू महंगा। इरादा क्या है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं? अगर मैं आपसे एक-एक चीज़ पर बात करूं, तो सबसे पहले एक चीज़, जिस पर आपसे बात करना चाहता हूं, वह यह है कि यह जो महंगाई बढ़ रही है, यह आपकी बढ़ाई हुई महंगाई है। मैं आपसे ख़ास तौर से एक-दो बातें जरूर कहना चाहता हूं। इस महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। आप देखें, आप बाजार में किसान को जो रेट देते हैं — मैं इसलिए सरकार से कह रहा हूं, क्योंकि आज़ादी के बाद से इस सरकार से बड़ी * सरकार आज तक कोई पैदा नहीं हुई है। आप जो कहते थे कि हम किसान को पचास

*Expunged as ordered by the Chair.

प्रतिशत बढ़ाकर देंगे, आपने वह बढ़ाकर नहीं दिया। उसको, जो पैदावार करता है, उसका दाम नहीं मिलता है, पर बाज़ार में आते-आते यह महंगाई क्यों बढ़ जाती है, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। किसान पचास रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दाल बेच रहा है, लेकिन बाज़ार में दो सौ रुपये में आई है, तब ये डेढ़ सौ रुपये कौन खा रहा है? यह डिफ़रेंस किसके पास जा रहा है? मैं आपको बताता हूं कि यह कहां जा रहा है। मुंबई में छापा पड़ा। मुंबई में सत्तर प्रतिशत दाल कालाबाज़ारी और चोरबाज़ारी में रिकवर हुई। उनके घर से, जो रसीद मिली, उसमें उन्होंने टैक्स दिया था, चंदा आपको। क्या आप चंदे के एवज़ में यह महंगाई बढ़ा रहे हैं? किसान को उतना ही मिल रहा है और उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ रहा है, तब इसके बीच की महंगाई क्यों बढ़ रही है? आप कहते हैं कि पैदावार कम हुई। मैं कहना चाहता हूं कि अकेले दाल की पांच परसेंट पैदावार कम हुई है, लेकिन रेट बढ़ गया सवा सौ परसेंट। ऐसा क्यों? मेरा सीधा-सीदा आरोप है कि आप अपने राज में वेल्थ टैक्स तो कम करते हैं, लेकिन आप गरीब पर लगने वाला टैक्स बढ़ाते हैं, क्योंकि आप गरीबों के विरोधी हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, हम तो गरीबों की बात कर रहे हैं।..**(व्यवधान)**..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): प्रमोद तिवारी जी, आपकी पार्टी से बोलने वाले अभी पांच सदस्य और हैं।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, हम बात कर लेंगे। हम कोलकाता में बात कर लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप सुनिए। आपकी पार्टी के पांच और स्पीकर्स हैं।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, हम उनसे वह बात कर लेंगे, लेकिन आप तो हमारे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आपका टाइम ओवर है। आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद तिवारी: सर, इतने में तो हो गया था। सर, बस दो मिनट। मैं एक बात कहकर इसको खत्म करना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि इस सरकार के आने के बाद केवल एक ही तबका खुश हुआ है और वह है पूंजीपतियों का। जब टैक्स कम करना होता है, कर्जा कम करना होता है, तो जिन लोगों के हवाई जहाज पर बैठकर ये घूम रहे थे, उनका तो ये एक झटके में 2000 करोड़ रुपये माफ़ कर देते हैं, लेकिन हमारा किसान, जिस पर बकाया है, अगर वह वापस देने में पंद्रह मिनट की देर कर दे, तो उसे जेल भेज देते हैं। ...**(व्यवधान)**... हम इनसे पूछना चाहते हैं कि यह आपका कौन-सा फॉर्मूला है कि आपका पूंजीपति तो आराम से रह रहा है, सुखी है, लेकिन हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है। हमारा किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप मुझे आज़ादी के बाद से एक साल का फ़िगर दे दीजिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मेरे बाद बीजेपी को बोलना है, वह साल बता दो, जिस साल में किसानों ने इतनी आत्महत्याएँ की हों, जितनी आपके आने के दो साल के अंदर की हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं। किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है, आम आदमी मर रहा है, सरकारी कर्मचारी मर रहा है, लेकिन अगर कोई हँस रहा है, तो इस समय भाजपा सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पर महंगाई की मार नहीं है, वरना आम जनता पर महंगाई की मार है।

मैं आपसे विनम्रतापूर्वक सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं अपनी स्पीच बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, इसके बाद टाइम नहीं मांगूंगा। मैं पूरी तरह से सीधा-सादा इल्ज़ाम

[श्री प्रमोद तिवारी]
लगाता हूं कि इस देश में आज की बढ़ी हुई महंगाई का जिम्मेदार अगर कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी नीति, उसके संरक्षण में पलने वाले जमाखोर और कालाबाज़ारी करने वाले लोग हैं। आज इनका एक गठबंधन है। इनका, जमाखारों और कालाबाज़ारियों का एक अपवित्र गठबंधन है, जिसकी वजह से बाज़ार में महंगाई बढ़ रही है और उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। जब आप यहां बैठेंगे, तो आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): एक बात है, मैं आपको inform करना चाहता हूं कि आपने जो, सावन का अंधा बोला है, *

श्री प्रमोद तिवारी: उपसभाध्यक्ष जी, "सावन के अंधे को सिर्फ हरा-हरा दिखाई देता है", यह कहावत है। ...**(व्यवधान)**... मैंने इनको अंधा नहीं कहा। ...**(व्यवधान)**... मैंने इनको कालाबाज़ारियों को ...**(व्यवधान)**... देने वाला अंधा नहीं कहा।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY):* Now, Shri Shwait Malik.

श्री श्वेत मलिक (पंजाब): ऑनरेबल सर, मुझे यह देख कर बड़ा अचरज हुआ कि जिन्होंने 60 वर्ष तक लंबा शासन किया, वे आज कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएँगे! इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता था कि देश की जनता ने आजादी के बाद लंबा शासन करने का सुअवसर सामने बैठे माननीय सदस्यों की पार्टी को दिया और वे आज दो वर्ष की सरकार से यह कह रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएँगे। मैं यह समझता हूँ कि इनका विश्वास ...**(व्यवधान)**... इनका विश्वास अपनी सरकारों में नहीं था। ...**(व्यवधान)**... मैं यह मान कर चलता हूँ कि इनका विश्वास अपनी पार्टी और सरकार से उठ गया था, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी/एनडीए की है, इनको भी मालूम है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तभी ये माँग कर रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएँगे। ...**(व्यवधान)**... आज जो चुनाव में लोक सभा का निर्णय हुआ, लोक सभा के चुनाव में जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि बहुत वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जीत दी, तो उसके कारणों में जाना बहुत जरूरी होगा कि सामने बैठे मित्रों की पार्टी की जो एक जबर्दस्त पराजय हुई, तो उसके कारण क्या थे। यह वह पार्टी थी, जो कहती थी कि गरीबी हटाओ, यह वह पार्टी थी, जो कहती थी कि महँगाई घटाओ और अवस्था क्या हो गई थी — मैं इनके 10 वर्षों के शासन की बात करूँगा — कि मानो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी अर्थशास्त्री की सरकार की। यही कारण था कि देश की जनता जब त्राहि-त्राहि कर रही थी और एक-एक दिन, एक-एक घड़ी गिन रही थी कि कब चुनाव आए, तो हम इनको एक सबक सिखाएँ। यही कारण था कि आप लोग लोक सभा में आज तक की न्यूनतम संख्या में आ गए हैं और दो साल के बाद इस हाउस में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है कि यहां भी न्यूनतम संख्या होने वाली है। उस महँगाई पर जब आप बात करते हैं, तो यह बड़े अचरज की बात है। वह प्याज जब आसमान को छू गया था और हम निर्यात कर रहे थे, ये बात करते हैं महँगाई की कि महँगाई कब हटेगी। 60 वर्ष शासन करने वाले यह बात करते हैं। जब इनको सुअवसर मिला था, तो महँगाई आई क्यों? अगर यह नहीं आई थी, तो जनता ने

---

* Expunged as ordered by the Chair.

वह फैसला क्यों दिया, जो एक ऐतिहासिक फैसला है? मैं धन्यवाद करूँगा माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का और माननीय श्री अरुण जेटली जी का, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, कि ऐसी स्थिति, जब मानो देश का शासन से विश्वास उठ गया था, उस समय आकर इन्होंने देश को संभाला। आज उस देश का नाम सारी दुनिया में गौरव के साथ लिया जा रहा है। ये वे मोदी जी हैं, जिन्होंने दो वर्ष में इतिहास create किया, हर पक्ष को देखा। आज महँगाई के लिए जो कहा जा रहा है, एक दाल के लिए जो कहा जा रहा है, वह crop मौसम के ऊपर निर्भर है और वह ठीक हो जाएगी। इनको भी मालूम है कि उसका कारण क्या है। यह ठीक हो जाएगी, लेकिन इनको बाकी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। क्या कारण है कि दो वर्ष के शासन के बाद जितने सर्वे हो रहे हैं, उनमें मोदी जी सर्वप्रिय प्रधान मंत्री के रूप में सब शहरों में उभर कर आ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): शेखर जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री श्वेत मलिक: अगर जनता उनके साथ होती, ...**(व्यवधान)**... अगर महँगाई पर जनता उनके साथ होती, तो यह निरंतर हार का सामना नहीं करना पड़ता। ...**(व्यवधान)**... सरकार ने महँगाई पर कंट्रोल करने के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं उसका विवरण देने जा रहा हूँ। "Exports of onion were restricted through imposition of minimum export price when prices were rising high; retail sale of onion was undertaken from the stock held by NAFED and other organizations; imported 2,000 metric tons of onion from Egypt and China as no demand from the States was received..." इसके बाद जो दालों के लिए किया गया, export of all pulses was banned. Import of pulses was allowed at zero import duty. Stock limit on pulses was extended. Government imported 5,000 MT of tur from other countries. मैं तो एक छोटा डेटा दे रहा हूं कि इस सरकार के द्वारा इम्पोर्ट को घटाया गया और रिज़र्व को बढ़ाया गया। हमारे भाई, प्रभात झा जी ने अभी डिटेल में सब बताया है, आपके आंकड़े भी बताए हैं और हमारी सरकार के प्रयास के संबंध में भी बताया है। हमारी सरकार, चाहे वेजिटेबल्स हों, दालें हों, ऑयल हो या अन्य मूलभतू सुविधाएं हों, उन सबके मूल्य नियंत्रण का पूरा प्रयास कर रही है। आपको इसमें सहायक होना चाहिए कि एक अच्छी सरकार वह काम कर रही है, जिसको आप 60 वर्ष तक नहीं कर सके। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस प्रकार के विरोध से न तो मोदी जी का मनोबल घटेगा और न ही सरकार का मनोबल घटेगा। इसमें जो असली निर्णायक है, वह है भारत की जनता। अब भी जो चुनाव हुए, हमारे पक्ष को जो जनमत मिल रहा है, उससे यह सिद्ध होता है कि जनता क्या सोच रही है। जनता को पूरा विश्वास है कि यह देश श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में परम वैभव पर पहुंचेगा और एक बार विश्व शक्ति बनेगा और हर भारतवासी का जो सपना है, वह अवश्य पूरा होगा।

श्री अशोक सिद्धार्थ (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मूल्य वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की चार-चार बार मुख्य मंत्री रहीं, परम आदरणीया बहन जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे एक साधारण से दलित परिवार में पैदा हुए बेटे को देश के सर्वोच्च सदन में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया।

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

मान्यवर, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण और लोकमहत्व के विषय पर मैंने सदन के सम्मानित सदस्यों की बातों को बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया है। जब से मैंने होश संभाला है और जब से राजनीति में मेरी रुचि बढ़ी है, तब से इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी और देश की सामाजिक गैर-बराबरी की व्यवस्था पर सदन और सदन के बाहर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं केवल चर्चाओं तक ही सीमित रही हैं। आज आजादी के 69 वर्ष हो गए, इन 69 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा बजट सेशन गया होगा या कोई ऐसा सत्र रहा होगा, जिसमें महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी पर चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन महंगाई के कारण क्या हैं, आज तक किसी भी राजनैतिक दल ने उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं की है।

मान्यवर, मैं सदन के सामने अपने विचार रखना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि महंगाई केवल रोजमर्रा की वस्तुओं, दाल, टमाटर, प्याज, आलू, खाद, बीज, डीज़ल, पेट्रोल या जिन वस्तुओं के नाम हमारे सदन में गिनवाए जाते हैं, उन वस्तुओं के दाम बढ़ने ही नहीं हैं, इसके अलावा भी इसके कुछ कारण हैं। महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण मुझे नज़र आता है, उसका सबसे सीधा संबंध गरीबी और बेरोज़गारी से है। जब तक हम गरीबी और बेरोज़गारी को नहीं समझेंगे, तब तक हम महंगाई को ठीक से समझ नहीं सकते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो सबसे पहले गरीब और बेरोजगार की थाली से खाने-पीने की चीजें गायब होने लगती हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो जो जरूरी वस्तुएं होती हैं, उसमें गरीब और बेरोजगार व्यक्ति को कटौती करनी पड़ती है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि गरीबी और महंगाई की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह सम्मानित सदन और देश की आम जनता इस बात से असहमत नहीं हो सकती कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के लगभग 80 प्रतिशत लोग महंगाई और गरीबी के कारण बेहद अपमानजनक स्थितियों का सामना कर रहे हैं। रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है, उससे इस देश का गरीब, इस देश का बेरोजगार युवा, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, सभी प्रभावित हुए हैं।

महोदय, अंग्रेजों की दो सौ वर्षों की गुलामी के बाद जब यह देश आजाद हुआ था, तो देश की बहुसंख्यक जनता को यह उम्मीद जगी थी कि स्वतंत्र भारत में उन्हें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और गैर-बराबरी की व्यवस्था के अपमान से छुटकारा मिलेगा, लेकिन आजादी के 69 वर्षों के बाद भी क्या इस देश की बहुसंख्यक जनता को इन चीजों से छुटकारा मिला है? यह मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ। आज आजादी के 69 वर्षों के बाद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर कोहिमा तक, पूरे देश के गांवों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज भी इन गांवों में व्यक्ति जाति के साथ पैदा होता है और जाति के साथ मर जाता है। हमारे देश के नीति-निर्माताओं ने, हमारे देश पर शासन करने वाली राजनैतिक पार्टियों ने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की चर्चा तो की, नीतियां तो बनाईं, लेकिन उनको जमीनी हकीकत पर उतारने का काम नहीं किया। क्या कारण है कि जो देश कभी "सोने की चिड़िया" कहलाता था, वह भारत जो विश्व को शांति का संदेश देने वाला भारत आज गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने वाला देश बन गया है? क्या कारण है कि हमारी राजनैतिक पार्टियों ने अतीत के भारत का गौरव-गान तो किया, लेकिन अतीत के गौरव को हासिल करने के लिए लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया? इसका प्रमाण है कि आज भी इस देश में मौजूद गैर-बराबरी की व्यवस्था, गरीबी व बेरोजगारी के कारण अपराध की दुनिया

में पलायन करता नौजवान, आत्महत्या करता देश का अन्नदाता किसान और आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करने पर मजबूर है। हमारे देश की राजनैतिक पार्टियों ने चाहे वह सत्ता पक्ष में हैं, या जो आज विपक्ष में बैठी हैं, इन राजनैतिक पार्टियों ने क्यों नहीं इस देश की बहुसंख्यक जनता को मान-सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का काम किया?

मान्यवर, यह भारत जो "जिओ और जीने दो" की भावना में विश्वास रखता था एवं "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" के सिद्धांत को मानता था, जो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने इस देश में दिया, आज उस सिद्धांत की हत्या हो गई। आज पूरे देश में "पूंजीपति हिताय और उद्योगपति सुखाय" का नारा लगाया जाता है। आज हमारी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जब सोलहवीं लोक सभा के चुनाव हुए थे, तो इन लोगों ने बड़े जोर-शोर से नारा लगाने का काम किया था कि "बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार"। इन्होंने बड़े ज़ोर-ज़ोर से नारा लगाया था- 'महँगाई इस देश को छोड़ कर जाने वाली है, क्योंकि अच्छे दिन आने वाले हैं।' इन्होंने नारा लगाया था- 'बीजेपी का पहला काम, लगेगी महँगाई पर लगाम।' इन्होंने कहा था- 'सबका साथ, सबका विकास।' लेकिन मान्यवर, आज जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, तो हमारे तमाम सीनियर सम्मानित सदस्यों ने महँगाई के कारणों पर विचार किया कि जमाखोरी के कारण और बिचौलियों के कारण महँगाई बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से मान्यवर, इन्होंने जो नारा लगाने का काम किया था कि 'सबका साथ, सबका विकास', वह नारा सच्चाई में नहीं था। इनका नारा सच्चाई में यह है कि 'पूँजीपतियों का साथ, पूँजीपतियों का विकास।' 'सबका साथ, सबका विकास' इनका नारा नहीं है। अगर 'सबका साथ, सबका विकास' इनका नारा होता, तो चुनाव के दौरान इस देश के जिन उद्योगपतियों से इन्होंने सहयोग लेकर, बड़े-बड़े प्रचार करके, जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम किया था और सत्ता में आए थे और आज जब सत्ता में पूर्ण बहुमत से आ गए, तो वादों को पूरा करने का कार्य करते। अभी हमारे मित्र इधर के लोगों को कह रहे थे कि आप 44 पर आ गए। मैं एक शेर के माध्यम से अपने मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यह समझाना चाहता हूँ कि —

'बुलंदी किसके हिस्से में देर तक रहती है,
बड़ी ऊँची इमारत हमेशा खतरे में रहती है।'

इनको यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका वह दौर भी था कि जब ये दो थे और आज ये पूर्ण बहुमत में हैं। हमने जब से राजनीति में होश सम्भाला है, 1980 में thumping majority में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है और वह भी आज 44 पर आ गई है। कारण, जो जनता वोट देकर इस देश की पार्टीज़ को सिर पर बिठाने का काम करती है, शासन पर बिठाने का काम करती है, उसी जनता के साथ जब छलावा होता है, उसके साथ धोखा होता है, तो वही जमीन में भी मिलाने का काम करती है।

मान्यवर, महँगाई पर नियंत्रण के लिए भी इन्होंने वादा करने का काम किया था। इन्होंने वादा किया था कि हम महँगाई पर नियंत्रण रखने के लिए 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' बनाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा था कि किसान अन्नदाता होता है, जो पूरे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। इन्होंने 'अन्नदाता सुखी भवः' का नारा देने का काम किया था और यह कहा था कि मेरी सरकार आएगी, तो कोई भी किसान हो, हम किसान की उपज का डेढ़ गुना मूल्य देने का काम करेंगे। दो वर्ष हो गए, दो वर्षों में अगर हम आज़ादी के इतिहास को देखें, तो किसी

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

4.00 P.M.

भी सरकार के समय दो वर्षों के कार्यकाल में जितने किसानों ने आत्महत्याएँ कीं, उतनी किसी सरकार के समय में आत्महत्याएँ नहीं कीं। खास तौर से जहां-जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या हरियाणा हो, वहां पर किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएँ करने का काम किया है।

सर, इन्होंने एक वादा और किया था कि मैं देश के गरीब नौजवानों को, बेरोज़गार नौजवानों को प्रतिवर्ष दो करोड़ रोज़गार देने का काम करूँगा। मैं सरकार में बैठे लोगों से जानना चाहता हूँ कि इन दो वर्षों में दो करोड़ के हिसाब से चार करोड़ रोज़गार बनते हैं, तो कितने रोज़गार अभी तक सरकार ने दिए हैं? क्योंकि महँगाई का सम्बन्ध, गरीबी का सम्बन्ध बेरोज़गारी से है और बेरोज़गारी का सम्बन्ध गरीबी से है। कोई आदमी इसीलिए गरीब है, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। आदमी के पास रोज़गार नहीं है, इसीलिए वह गरीब है। यह सीधी-सीधी बात है।

इन्होंने एक और वादा किया था कि 'देश की गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए जो विदेशों में काला धन जमा है, उसे मैं 100 दिनों के अन्दर वापस लाकर हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख रुपये देने का काम करूँगा।' मान्यवर, यह सोशल मीडिया का जमाना है। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था। यह एक सच्ची घटना है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। दिन का सफर था, मैं ट्रेन में बैठा था। ट्रेन में एक मां अपने बेटे को, जो छः-सात साल का बच्चा था, उसको अंग्रेज़ी के महीने पढ़ा रही थी। वह कह रही थी- 'जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल'.. और वह उन महीनों के दिन भी बता रही थी कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28-29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, आदि। इस तरह से वह उसे सभी महीनों के दिन गिना रही थी। लेकिन उस बच्चे ने बरबस ही अपनी मां से पूछ लिया कि मां, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं, तो फरवरी में ही क्यों 28 या 29 दिन होते हैं? उस मां के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस मां ने बच्चे का मन बहलाने के लिए उस बच्चे से कहा, बेटा, फरवरी में 28 या 29 दिन इसलिए होते हैं, क्योंकि मोदी काका जी ने कहा है कि विदेशों में जो काला धन है, वह 30 फरवरी को आने वाला है। ....**(समय की घंटी)**... मान्यवर, यह हंसने की बात नहीं है। यह उस मां की बात है। वह मां भी इस बात को समझती है कि देश में अब काला धन न वापस आएगा और न किसी गरीब के खाते में 15 या 20 लाख रुपए जाएंगे।

मान्यवर, आज मेरी मेडन स्पीच है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद तिवारीः मैं समझ नहीं पाया। मोदी काका ने क्या कहा था? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः कृपया आप बैठिए। चूंकि आपकी मेडन स्पीच है, इसलिए आपके दो मिनट और बाकी हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अशोक सिद्धार्थः मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला। आदरणीय बहन जी की कृपा से मुझे विधान परिषद में बोलने का मौका मिला था। मेरे मित्रों, मेरे सीनियर साथियों ने महंगाई के ऊपर तमाम तरह की बातें कीं और सत्ता पक्ष के मित्रों ने भी बताने का काम किया, लेकिन सच्चाई यह है कि आज

गरीब महंगाई से प्रताड़ित है, महंगाई से परेशान है। आज आम जनमानस महंगाई के बारे में क्या कहता है? वह कहता है कि पेट कर रहा है रात-दिन मुझसे यही सवाल, एक साथ कब आएंगे रोटी, सब्जी और दाल? मान्यवर, आज गरीब की थाली में रोटी, सब्जी के साथ दाल नहीं होती है, दाल होती है, तो सब्जी नहीं होती है। आज महंगाई की स्थिति यह है कि गरीब को अगर दाल मिलती है, तो चावल नहीं मिलता है, अगर चावल मिलता है, तो रोटी नहीं मिलती है, रोटी मिलती है, तो सब्जी नहीं मिलती है। सब्जी में खास तौर से आलू, जो गरीब का पसंदीदा भोजन होता है, वह नहीं मिलता है।

मान्यवर, मैं फर्रूखाबाद जिले के कायमगंज तहसील का रहने वाला हूँ। वहां आलू भारी मात्रा में होता है। जब वहां आलू पैदा होता है, आलू का सीज़न होता है, उस समय किसान से आलू चार या पांच रुपए प्रति किलो की दर से बिचौलिए व्यापारी खरीद लेते हैं और वही आलू आज बाजार में 30, 35 या 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। इस तरह से गरीब किसान को क्या मिलता है? मैं यह सत्ता पक्ष से जानना चाहता हूँ।

मान्यवर, आपने जैसा कहा कि दो मिनट का समय है, मैं दो मिनट में बहुत ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आपके वह दो मिनट भी खत्म हो गये। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अशोक सिद्धार्थः मान्यवर, बीजेपी यह कहा करती है, बीजेपी के लीडर्स अक्सर यह कहा करते हैं कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये यह क्यों नहीं कहते हैं कि छुआछूत मुक्त भारत बनाओ, ये यह क्यों नहीं कहते हैं कि दलितों और महिलाओं के सम्मान और अस्मिता का रक्षक भारत बनाओ, ये यह क्यों नहीं कहते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई मुक्त भारत बनाओ? अगर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को रोकने के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ प्रयास किए होते, मूल्य स्थिरीकरण कोष व मांग और आपूर्ति के अनुरूप अपनी नीतियां बनाई होतीं, तो आज देश के सर्वोच्च सदन में कई-कई बार महंगाई पर चर्चा नहीं करनी पड़ती। ...**(समय की घंटी)**... मैं अपनी बात एक कविता के साथ समाप्त करूंगा। चूंकि मेरे पिता कवि थे, इसलिए थोड़ा-सा असर मेरे अंदर भी है। मान्यवर, मैंने एक कविता लिखी है, जो इस प्रकार हैः—

"महंगाई के चाबुक से जब जन-जन को पिटते देखा।
व्यथित हो उठा अंतर्मन जब अपनों को छलते देखा।।
महंगाई के चाबुक से जब अपनों को पिटते देखा।
व्यथित हो उठा अंतर्मन जब अपनों को छलते देखा।।
बेबस किसान मजलूमों पर क्यों महंगाई की मार है।
मूक बना मोदी शासन क्या अच्छे दिन ही आज हैं।।
रेल किराया माल भाड़ा महंगी सब्जी दाल है।
भूख प्यास से मरती जनता जनमानस बेहाल है।।
किया दिखावा जनता को अच्छे दिन की सरकार में।

[श्री अशोक सिद्धार्थ]

मोहताज निवाले को जन-जन बस महंगाई की मार है।।
महंगाई का वायरस फैला सबमें हाहाकार है।
पूंजीपति लॉबी मौज में पर बेबस ये सरकार है।।
महंगाई के चाबुक से जब अपनों को पिटते देखा।
व्यथित हो उठा अंतर्मन जब अपनों को छलते देखा।।"

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम!

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): अगर आप यह कविता पहले पढ़ देते तो भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ती। श्री प्रफुल्ल पटेल जी।

श्री प्रफुल्ल पटेल (महाराष्ट्र): मान्यवर, एक और सत्र, एक और साल और इस सदन में तकरीबन वही चर्चा कि महंगाई हमारे देश में बहुत बढ़ गई है, गरीब आदमी जूझ रहा है, लोग परेशान हैं और यह चर्चा निरंतर करते जाने के बाद भी इसका कोई समाधान हम ढूंढ़ नहीं पाते हैं, यह हमारे सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता और दुख का विषय है। स्वाभाविक है कि जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी ही ज्यादा बनती है। मुझे याद है कि जब हम सरकार में थे और पासवान जी की जगह पर हमारे नेता पवार साहब बैठा करते थे। तो यही चर्चा और हमारे मित्र जो यहां पर हैं और खासकर के वह मित्र मेरे सामने मुस्करा रहे हैं, यह उस बात को जरा ज्यादा प्रोत्साहन देने का भी काम करते थे, लेकिन मेरे कहने का मकसद यह है कि महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है, गरीबी उससे भी बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और इसका कहीं न कहीं हल निकालना यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि जब हम भी सरकार में थे, मैं थोड़ी पहले अपने पर टीका करता हूं, बाद में आप पर करूंगा। हमारे टाइम पर प्लांनिग कमीशन ने एक कुछ रिपोर्ट निकाली थी कि 30 रुपए के करीब अगर रोज की कमाई होती है तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाना चाहिए। अगर हम उसको मानते हैं कि यह बहुत बड़ी आमदनी है और उससे हमारी दो वक्त की रोज़ी-रोटी चल जाती है तो हम गरीबी मुक्त हो गए, इस सोच के साथ अगर हमारी राष्ट्रीय नीति क्योंकि योजना आयोग राष्ट्रीय नीति का एक प्रमाण होता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित हम सब लोगों के लिए एक चिंता का विषय बनता है। केवल हम लोग यही बात कर रहे हैं कि टमाटर के दाम क्या हो गए, आलू के दाम क्या हो गए, दाल के दाम क्या हो गए। निश्चित एक विषय होता है, क्योंकि वह दिन-ब-दिन हर गरीब की थाली का विषय होता है, लेकिन उसके साथ इतने बड़े देश में केवल एक वर्ग की बात न करते हुए आज किसान की भी बात करेंगे तो अच्छा होगा। किसान अनाज पैदा करता है, सब्जी वगैरह पैदा करता है। It does not end there, किसान भी तो एक उपभोक्ता है। अगर किसान अनाज या सब्जी या कुछ और पैदा करता है तो साथ में उसको दूसरी वस्तुओं को भी खरीदना है बाजार में जाकर। उसको भी अपना दिन-ब-दिन जीवन चलाना है। तो हम उपभोक्ता और किसान में अंतर न समझें। हमारे देश के हर वर्ग के व्यक्ति को कहीं न कहीं आज इस समस्या का सामना करना पड़ता है। Even middleclass, आज शहरों में रहने वाला, अगर हम सोचते हैं कि किसी की पंद्रह-बीस-पच्चीस हजार रुपए की कमाई शहर में होती है तो उसको कोई गरीबी का या महंगाई का असर नहीं होता, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको ज्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि उसकी आमदनी सीमित है, लेकिन उसके खर्च का जो तरीका है वह एक अलग तरह का होता है। सिटीज़ में you have to

see people spending on education. आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है? अगर हम प्राइस राइज़ की बात करते हैं तो price rise should not be only restricted to a few items of daily consumption. Education is a very expensive subject for most of the people. Even in small towns and small villages, you find people wanting their children to get good education. So, education has become very expensive. Transportation, आज शहर में कोई द्वारका में रहता है, तो कोई कहीं दिल्ली के मयूर विहार या कोई नोएडा में रहता है या कोई गुड़गांव में रहता है। उसका जो आने-जाने का ट्रांसपोर्टेशन है, वह कितना महंगा हो गया है! सारी चीजों को अगर हम लेंगे तो यह महंगाई... आज शहरों में किरायों का कितना बड़ा सिलसिला है। अगर एक छोटा आदमी, 20-25 हजार रुपए की आमदनी करने वाला दिल्ली में रहने की कोशिश करे और कहीं एकदम झुग्गी-झोंपड़ी के इलाके में भी सामान्य किराये पर जाएगा तो उसको दो-चार हजार रुपये सहज किराया देना पड़ेगा।

आज यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम महंगाई पर एक छोटे-से परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जबकि आज अगर हम देश में महंगाई के बारे में व्यापक तौर पर सोचेंगे तो यह हम सब के लिए एक चिन्ता का विषय है। इसलिए अब सरकार का दायित्व आता है। आपने इसके बारे में केवल दो-चार बातें कर लीं, अच्छी बातें कर लीं कि यह हो जाएगा, वह हो जाएगा; हमने दाल का इम्पोर्ट कर लिया, हमने वह कर लिया और केवल दाल इम्पोर्ट करने से आप सोचते होंगे कि इस महंगाई का सिलसिला खत्म हो गया। अगर आपने लोगों के लिए आलू या प्याज का इंतजाम कर दिया, जैसे कि आजकल यह फैशन हो गया है कि किसी एक राज्य अथवा दिल्ली में महंगाई हो गई, तो 15-20 ठेले कहीं-कहीं पर लगा दिए गए, दो-चार दुकानें खोल दी गईं एवं आपने कह दिया कि यहां "अपना बाजार" या "सुपर बाजार" में यह चीज़ किफायती दाम पर मिलती है और आपने समझ लिया कि हमने महंगाई की समस्या को सुलझा दिया है। **...(समय की घंटी)...** Sir, I have not even started. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I appreciate the way you are discussing. This is a very serious issue. ...(*Interruptions*)... But I am helpless. ...(*Interruptions*)...

SHRI PRAFUL PATEL: I know your problem. But I will solve it within a few minutes. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please solve it. ...(*Interruptions*)... Please solve the problem. ...(*Interruptions*)... ठीक है, बोलिए।

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, the issue is that the farm income must increase because India still lives in its villages. आज भी देश की जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है, जिसकी आय का जरिया आज भी किसानी है और वह कृषि के माध्यम से अपना जीवन-यापन करता है। आज कृषि की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। उसकी पैदावार की कीमतों के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा। गांव में उसके लिए उसके हाथ में जितना मिलता है और शहर में अंतिम उपभोक्ता के हाथ में वह चीज़ जिस कीमत पर पहुँचती है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं। पासवान जी, आपको भी मालूम है कि cold

[श्री प्रफुल्ल पटेल]
chain तथा बाकी बहुत सारी चीज़ों में निश्चित रूप से प्रगति हुई है, लेकिन जिस मात्रा में वह प्रगति होनी चाहिए, जिस गति से वह होनी चाहिए और उसका जो सीधा फायदा किसानों को मिलना चाहिए, वह कहीं न कहीं हम अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। आप एमएसपी की बात करते हैं। Bulk of the procurements of the farmers is through MSP. आज आप एमएसपी की कीमतों गेहूँ में 70 रुपये बढ़ा देते हैं, चावल में 60 रुपये बढ़ा देते हैं। आपको लगता होगा कि महंगाई केवल एक ही चीज़ की है, लेकिन आज किसान के खाद की क्या कीमत है? इस बार आपने उसकी कीमत थोड़ी घटाई, लेकिन खाद की कीमत और मजदूरी...

एक माननीय सदस्यः आज़ादी के बाद पहली बार ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रफुल्ल पटेलः ठीक है, भाई। पहली बार इसलिए कि पेट्रोलियम के दाम कम हुए हैं। मुझे आप लोग क्या समझा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... Do you know what the fertilizer is made of? ...(*Interruptions*)... Maximum feedstock for making fertilizers is petroleum products. It is naphtha. If you do not know this, then, why are you making this statement? I am taking responsibly. मैंने आपके ऊपर कोई टीका-टिप्पणी तो नहीं की! मैं तो केवल इस देश की राष्ट्रीय समस्या के बारे में यहां पर जिम्मेदारी पूर्वक बात कर रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलिए।

श्री प्रफुल्ल पटेलः मैंने तो अपनी सरकार को भी क्रिटिसाइज़ किया कि योजना आयोग ने हमारी सरकार के वक्त क्या कहा था। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा हटकर अपनी बात कह रहा हूँ कि आज यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है और हम इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज किसान को हर चीज़ की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आज मजदूरी कितनी महंगी हो गई है! आज किसान को मजदूर मिलता नहीं है और जब मिलता भी है तो उसको इतना भुगतान करना पड़ता है कि उस पैदावार को वह जिस कीमत पर बेचता है, उसमें उसको घर चलाना मुश्किल हो जाता है। कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अधिक बारिश हो जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं से किसान आज जूझ रहा है। ...**(समय की घंटी)**... Mr. Vice-Chairman, Sir, even in the cities, the biggest problem for most of the people is how to make two ends meet. I think, this is a big issue. नई नौकिरयां तैयार नहीं होती हैं। The biggest issue, today, is of unemployment. Every person has children at home who are educated. But, at the end of the day, there is no job. In fact, the real issue today is not jobs, but the net addition of jobs. आज जितनी नौकिरयां हैं, उनमें से पुरानी जाती हैं और दूसरी खड़ी होती हैं, लेकिन रोजगार के नये अवसर आज हमारे देश में पैदा नहीं हो रहे हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। इसलिए एक और सत्र, एक और चर्चा, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। यह हमारे लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है।

सरदार बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): सर, आज हाउस में जो discussion हो रही है, उसमें मैं दोनों तरफ के सदस्यों को सुन रहा था। मैं ऑनरेबल पटेल साहब की praise करता हूं, जिन्होंने neutral बात की। हम जब यहां पर बोलते हैं, तब कई दफा हम यह नहीं सोचते नहीं कि इस

देश के लोग हमें देख रहे हैं, कई दफा वे टीवी पर टेप भी करते हैं, शायद यह हमें पता नहीं है। हम जब बोलते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी लगे और दूसरी पार्टी माड़ी हो, लेकिन हमारे यहां अच्छा या बुरा कहने से लोगों पर उसका असर नहीं होता, यह सब सिर्फ कुछ देर अखबार में आ जाता है और उसके बाद जो लोगों की असली ज़िन्दगी है, उस समय लोग देखते हैं। इसलिए यह जो महंगाई पर चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं है कि बात थोड़ी सी है और महंगाई इतनी ज्यादा है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। इसका कारण क्या है? सोचने वाली बात यह है कि हम हर साल महंगाई पर चर्चा करते हैं, केवल आज ही चर्चा नहीं कर रहे। जैसे पटेल जी ने कहा, जब इनकी सरकार थी, तब भी हम इनके खिलाफ बड़ा झगड़ा करते थे और उससे पहले भी तीस-चालीस साल से हम सड़कों पर उतरते थे, कभी असेंबली का तो कभी पार्लियामेंट का घेराव करते थे, कभी सड़कों पर महंगाई के खिलाफ बड़ी-बड़ी कांफ्रेंस करते, लेकिन इसका जो हल है, वह किसी ने अभी तक नहीं सोचा कि इसका कारण क्या है और इसको हल कैसे करें। यह देश की बदकिस्मती है। यही कारण है कि देश में अफरा-तफरी मच रही है। हर वर्ग में जो बगावत हो रही है, उसका यही कारण है कि लोगों का गुज़ारा नहीं होता है, employment है नहीं और महंगाई बढ़ गयी है। ऐसे में लोग क्या करें? वे झगड़े ही तो करेंगे। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं वह किसी एक के विरुद्ध या एक के पक्ष में नहीं कहना चाहता। हम बीजेपी के एलाइज़ हैं, यह बात दुरुस्त है, लेकिन कोई जादू तो है नहीं कि दो साल में महंगाई दूर हो जाएगी। यह समस्या तो बहुत समय से चली आ रही है। हम सन् 2004 या 2005 में 1.3 मिलियन टन दालें इम्पोर्ट करते थे, अब about 3.5 मिलियन टन इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हुई, इसका कारण क्या है? कारण है, किसान। जिस किसान के बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं। हम बातें करते हैं, लेकिन जो किसान आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसकी बात हम कभी नहीं करते। जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम कब तक इम्पोर्ट करते रहेंगे, किस-किस चीज़ को इम्पोर्ट करेंगे। कभी sugar की कमी हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी किसान गन्ना सड़कों पर फेंकता है तो कभी वह महंगा हो जाता है। अब sugar इतने high price पर हो गयी है। इसी प्रकार कॉटन है। पिछले तीन साल कॉटन बड़े low price पर रही और अब कितने high price पर हो गयी है। इसी तरह पिछले साल onion सौ रुपए किलो की दर से दिल्ली में बिक रहा था, इस दफा गांव में वह आठ आने किलो नहीं बिका और गुजरात में, महाराष्ट्र में उसे लोगों ने सड़कों पर फेंका, कभी यहां 50 रुपए किलो की कीमत पर potato बिकता है और कभी उसे लोगों ने सड़कों पर फेंका, हमारे जालंधर में कई दफा लोगों ने ट्रालियां की ट्रालियां फेंकी, क्योंकि उसे आठ आने किलो की दर से भी कोई नहीं लेता। इसका कारण क्या है, यह सोचने की बात है। हम सोचते हैं कि यह जो महंगाई है, यह किसान के सिर पर है। किसान की पैदावार की कम कीमत रखें तो महंगाई रुक जाएगी। देश की कितनी बदकिस्मती है कि अगर महंगाई बढ़ती है, price index बढ़ता है तो price rise के मुताबिक हिन्दुस्तान के सभी मुलाज़िमों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, मज़दूर कहता है, हमारी मज़दूरी बढ़े, ट्रक वाला कहता है, हमारा किराया बढ़े, लेकिन किसान के बारे में कभी कोई नहीं सोचता कि उसकी चीज़ का दाम बढ़े। अगर उसकी पैदावार की कीमत बढ़ जाएगी तो Price कमीशन कहता है कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी। देश में महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे, किसान मरता, मरता और मरता जा रहा है, लेकिन उसकी फसल का दाम नहीं बढ़ेगा। हम कितनी देर तक इम्पोर्ट करेंगे? आज potato की कमी हो गयी है, आज मूंग की कमी हो गयी है, आज मसूर की कमी हो गयी है, आज चीनी की कमी हो गयी है, इसके लिए लांग टर्म

[सरदार बलविंदर सिंह भुंडर]

पॉलिसी बनानी होगी। सर, मैं थोड़े लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं, क्योंकि टाइम कम है। जब तक आप हिन्दुस्तान के किसान को उत्साहित नहीं करेंगे, उसको assured price, assured yield, assured marketing — ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करें, ताकि उसकी समस्या का समाधान हो। अब wheat and paddy का glut आ रहा है, कभी इसकी shortage होती है, इसको diversify करके उधर जाएं, ताकि पैदावार बढ़े। एक सबसे बड़ी बात और है, पहले पटेल साहब बोल रहे थे, जब पवार साहब के पास वह महकमा था तो उन्होंने अपनी figure इसी हाउस में दी थी। 8.3 बिलियन डॉलर per year, wastage of food and food items हैं, जिसमें सभी आइटम्स आ जाते हैं, जिसमें vegetables भी आती हैं, जिसमें fruits भी आते हैं, pulses and wheat paddy भी आ जाता है। 8.3 बिलियन डॉलर per year — इसको आप अगर रुपए में जोड़ लें तो यह करोड़ों रुपए होगा। मैं तो इसकी गिनती कर नहीं सकता, लेकिन कोई अच्छा एक्सपर्ट करेगा। अगर इसको ही रोक लें, तो इससे ही देश बच जाएगा। इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है। इसके लिए जरूरत है कि बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ होने चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। जहां पर किसी चीज़ की शॉर्टेज है, वहां पर बड़े गोदाम हों और जहां पर ज्यादा सरप्लस है, वहां से दूसरी जगह पर जाएं। देश के किसी कोने में कमी है, किसी कोने में ज्यादा है, इससे बैलेंस हो जाए। ...**(समय की घंटी)**... प्रोड्यूसर को प्राइस मिले, कंज्यूमर को ठीक रेट मिले, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगाई है। आज ही नहीं, हर दो साल बाद महंगाई बढ़ती है और फिर एक साल बहुत डाउन चला जाता है, उसमें किसान मर जाता है। इसको रोकने के लिए हमें लांग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी अन्यथा बहस तो साल-दर-साल होती रहेगी, किसान रोता रहेगा, खाने वाला रोता रहेगा, हम बोलकर चले जाते रहेंगे और देश ऐसे ही चलता रहेगा, धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, जिसे पूरे सदन को गंभीरता से लेना चाहिए और खासतौर से सत्ता पक्ष को, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सारे वक्ता बोले और सत्ता पक्ष के दो वक्ता बोले, उन्होंने महंगाई पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया या कोई ठोस बात नहीं रखी। जहां भी जाओ, वे वही नारा लगाने लगते हैं — मोदी, मोदी, मोदी, मोदी। वे हर बात में, हर वाक्य में वही बोलते रहे और कोई ठोस जवाब नहीं दिया। यह बड़े दुख की बात है। ...**(व्यवधान)**... "हर-हर मोदी" कुछ भी बोलो, परन्तु यही बोलते रहोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। अब साल भर तक इंतजार कीजिए, उसके बाद ही दूसरा विस्तार होगा। तब तक के लिए क्यों आप इतना गला सुखा रहे हैं? इसलिए अब कोई ठोस बात बोलिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप ठोस बात बोलिए।

(उपसभापति महोदय *पीठासीन हुए)*

श्री राजीव शुक्ल: उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे मित्र सिद्धार्थ अशोक जी ने भी कहा कि किस तरह से नारे लगाए गए — "बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार", लेकिन सिद्धार्थ जी को मैं कहता हूं कि अब नारा बदल गया है — "बढ़ती जाए महंगाई की मार, क्यों लाए मोदी सरकार"। अब लोग ये नारा लगा रहे हैं कि "एक ही भूल, कमल का

फूल"। यह नारा जगह-जगह पर लगा है और मुम्बई में भी लगा है, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आई, क्योंकि 7.55 प्रतिशत मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जो कि एक चिंता की बात है। अब Consumer Price Index जो है, वह 5.77 परसेंट पर पहुंच गया है। ये दोनों बातें बहुत चिंता की हैं। जैसे कि लोगों ने इस बात को रखा कि 2014-15 में सिर्फ एक साल के अंदर चना दाल went up by 51 per cent, अरहर by 94 per cent, उड़द by 88 per cent, मूंग by 10 per cent, मसूर by 20 per cent. यह तो सिर्फ खाने-पीने के चीज़ें हैं। खाने-पीने की चीजें की बात तो रामविलास पासवान जी के डिपार्टमेंट में आती हैं। लेकिन बाकी चीजें पर भी महंगाई बहुत बढ़ गई है। Ministry of Statistics की रिपोर्ट के अनुसार the cost of education has increased by 13 per cent, housing; by 10 per cent, healthcare; by 14 per cent and electricity; by 8 per cent. महंगाई हर तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सब पहली बार हो रहा है। यह पहले भी हुआ है। हर समय कोशिश होती थी और महंगाई को रोक कर जनता को राहत दी जाती थी, लेकिन ये राहत हमें नहीं मिल रही है। एक बात हमारे मित्र ने कही कि होर्डिंग बहुत बढ़ गई है, जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यह बात चिंताजनक है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप को राज्य सरकार, मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए और उनका सहयोग भी लेना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं।

इम्पोर्ट की बात हुई। मैं प्रभात झा साहब को सुन रहा था। वे कह रहे थे कि पांच हजार मीट्रिक टन अरहर की दाल हमने इम्पोर्ट की। जब हमारी खपत चार लाख मीट्रिक टन की हर साल की है, तो पांच हजार मीट्रिक टन दाल इम्पोर्ट करने से क्या होगा? वह तो कुछ दिन के लिए आपके काम आएगी। वह दाल भी ऐसे पोर्ट्स पर आई, गुजरात, महाराष्ट्र के पोर्ट्स पर आई, वहां पर जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने उसकी होर्डिंग कर ली और वहां पर भाजपा की सरकारें हैं, तो उनको छापा डालकर या कुछ करके, उनको बाहर निकलवाना चाहिए था। आम जनता तक वे चीजें नहीं पहुंच पाईं। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए।

मैं सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा। आप कहते हो कि हम मदद करेंगे, MSP बढ़ाएंगे। किसी ने कहा कि बिचौलिए खा जाते हैं। जब प्रणब मुखर्जी साहब यहां पर वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि वे साउथ एवेन्यू के पास रहते हैं और आजादपुर मंडी में जो चीज़ 20 रुपये किलो मिलती है, वह साउथ एवेन्यू आते-आते 120 रुपये किलो हो जाती है। यह 100 रुपये 15 किलोमीटर के अंदर ही बढ़ाकर बिचौलिए लोग ले जाते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको एक रिटेल चेन बनानी पड़ेगी कि कैसे आप गांव तक जाकर, किसान तक जाकर सामान कलेक्ट करें और रिटेल चेन में पहुंचाएं। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह इसको लागू करे और MSP पहले से बताए। अगर आप दाल पर किसान का समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं, वैसे आपने बढ़ाया नहीं है, तो आप उनको पहले सूचित करें, ताकि वे दाल उगाएं। अगर हम उनको एक साल पहले बताएंगे कि हम आगे आपको यह देंगे, तो फिर वे लोग प्रोत्साहित होंगे और वे काम करने की कोशिश करेंगे, जो उन्हें करना चाहिए। आप वह नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसान बहुत परेशान हो जाता है।

एक और चीज है, यहां नक़वी साहब बैठे हैं तथा सारे लोग बैठे हैं, ये पहले Forward Trading की आलोचना करते थे। Forward Trading अभी भी वैसी ही है। अगर आप उस समय

[श्री राजीव शुक्ल]

इसके विरोधी थे, आलोचक थे, तो आपको इसको बदलना चाहिए था। उसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती है, क्योंकि Forward Trading पर आपने जो करना चाहिए था, आपने वह नहीं किया। Shanta Kumar committee की एक रिपोर्ट Food Corporation of India पर है। आपने उसको भी लागू नहीं किया है, जो FCI के बारे में आपके अपने ही MPs की रिपोर्ट थी। अब यह बात आई कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। अगर आज आप कर को देखें, tax देखें, 45 per cent tax, मतलब जनता कर से दबी जा रही है। ब्रिटेन में 45 per cent tax है, जो सबसे ज्यादा महंगा माना जाता है। इसी तरह से इंडिया में भी 45 per cent tax हो गया है। आपने Income Tax के अलावा स्वच्छता शुल्क लगाया हुआ है। यदि चाय पीने जाओ, तो भी स्वच्छता शुल्क लग जाता है। उसका यूज क्या हो रहा है, उस स्वच्छता शुल्क में दस हजार करोड़ रुपए कलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई योजना नहीं है कि देश की कैसे सफाई कर रहे हैं? यह कहीं नहीं दिख रहा है कि यह पैसा कहां जा रहा है। शुरू-शुरू में कुछ दिनों तक, एक होंते तो झाडू जरूर लगी थी और अखबारों में फोटे छपे थे। यह स्वच्छता शुल्क का पैसा कहां जा रहा है, जिसको आप टैक्स के रूप में ले रहे हैं, किसी को पता नहीं है।

इसके साथ-साथ आप किसान की मदद करने के लिए उसका भी सेस ले रहे हैं और किसान रो रहा है, तो यह पैसा कहां जा रहा है? हमारे वित्त राज्य मंत्री नए आए हैं, यदि ये इसका जवाब दें, तो हमें बेहद खुशी होगी। आज की तारीख में आप यह जान लीजिए कि ट्रेडर्स परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं और बड़े उद्योगपति परेशान हैं, क्योंकि रोजगार का सीधा लिंक entrepreneur से, उद्योगपति से है। इस देश का यूथ 2 per cent की दर से बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। देश के बड़े-बड़े उद्योगपति अपने बच्चों को बाहर सेटल कर रहे हैं। जब कोई उद्योगपति अपने बच्चे को बाहर NRI बनाता है, तो 50 या 100 करोड़ भेजता है, उसको वहां घर खरीदवाता है और उसका बिजनेस करवाता है। आज देश से बाहर पैसा जा रहा है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। मैं यहां कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह चिंता की बात है। क्योंकि आपने यह किया है कि हर चीज में arrest का, गिरफ्तारी का provision डाल दिया है। आपने Income Tax में गिरफ्तारी का provision डाल दिया है और FERA को FEMA में कन्वर्ट करके गिरफ्तारी का provision डाल दिया, कस्टम में गिरफ्तारी, एक्साइज में गिरफ्तारी और Service Tax में भी गिरफ्तारी, सीबीआई में तो करते थे। जब सब चीजों में आप गिरफ्तारी दोगे, तो व्यापारी, बिजनेसमैन, entrepreneur घबरा जाता है, क्योंकि उसको अफसर लोग धमकाते हैं कि यह करो, नहीं तो हम तुम्हें arrest कर लेंगे। इससे माहौल बिगड़ा हुआ है और बिजनेसमैन, entrepreneur सब घबराए हुए हैं। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर entrepreneur भाग जाएगा, तो रोजगार कौन देगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हैं, जिनसे काम चल सके। इसलिए आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि कैसे एक अच्छा वातावरण बनाएं। जो हमने वायदा किया था, उसके मुताबिक लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें और उनमें बिजनेस करने की एक स्थिति आए। आपको बेरोजगारी के लिए एक लम्बा-चौड़ा प्रोग्राम देना पड़ेगा, ताकि लोगों को फायदा हो। सिर्फ यह " हर-हर मोदी" का नारा देने से काम नहीं चलेगा।

क्योंकि—

"शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है,
और जिस शाख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है।"

सवा दो साल हो गए हैं और ढाई, पौने तीन साल बचे हैं, तो कुछ काम करके तो दिखाओ। अगर काम नहीं करोगे, तो सिर्फ नारे-नारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): उपसभापति महोदय, मुझे पहली बार बोलने का अवसर मिला है, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने दल के सचेतक महोदय का, जिन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया है, उनका और सभी माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करता हूं।

महोदय, हम यहां महंगाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह ऐसा विषय है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही ज्वलंत विषय है। ये बात सही है कि हर सत्र में, चाहे पार्लियामेंट में हों या फिर प्रदेश की विधान सभाओं में हैं... इस विषय पर कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में चर्चा होती रही है और आज भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक चर्चा हो रही है।

उपसभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ-जनों ने बहुत से विचार रखे हैं और बहुत सारे तर्क-वितर्क भी हुए हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार को दो-ढाई साल हुए हैं और हमने महंगाई को पूरी तरह से कम कर दिया है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी महंगाई पर कंट्रोल कर लेंगे।

महोदय, अगर हम तुलनात्मक रूप से विचार करें तो आप देखें कि इस देश पर किस पार्टी ने सब से अधिक समय तक शासन किया? अगर आज देश में महंगाई बढ़ाने का काम हमारा है, तो सब से अधिक जिम्मेदार आप हैं, जिन्होंने 50 साल से अधिक समय तक इस देश पर राज किया है। महोदय, इन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक नीतियां बनायीं और उन नीतियों के आधार पर हम आज चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी एनडीए की सरकार गांव के गरीब, मजदूर, किसान, बच्चे और बुजुर्ग — सब की आवाज को आवाज देने वाले, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। महोदय, एनडीए की सरकार ने पिछले दो सालों में ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं, ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिन्हें देश के इतिहास में लिखा जाएगा और हम यह कह सकते हैं कि चाहे आर्थिक नीतियों की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन की बात हो, चाहे इस देश की आंतिरक security की बात हो — इन सब में जिस तरीके से हमारी सरकार और सरकार के मुखिया ने जो कदम उठाए हैं, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं और ये देश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

उपसभापति महोदय, इस महंगाई को कम करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। ...**(व्यवधान)**... हम बता रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार रहिए। आप इतनी जल्दी हल्ला मत मचाइए। मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप अगर महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई के लिए सब से अधिक जिम्मेदार आप हैं। यूपीए की सरकार में जो सब से अधिक भ्रष्टाचार हुआ, वही महंगाई का सब से बड़ा कारण है, जिसने इस देश की महंगाई को प्रभावित किया। महोदय, मैं महंगाई के बहुत से कारणों को बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की पहल पर ही किसानों के हित में देश के इतिहास में पहली बार प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का निर्णय लिया गया। हम किसानों की हालत पर हर साल चर्चा करते रहे कि उन्होंने suicide कर लिया, इतने किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गयी। आज देश के प्रधान मंत्री जी ने किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान फसल बीमा योजना

[श्री राम विचार नेताम]
लागू करने का बहुत बड़ा कदम उठाया। यही नहीं, आगे चलकर देश के इतिहास में पहली बार, आज़ाद भारत में पहली बार रासायनिक खाद की कीमतों में कमी आई। आदरणीय शुक्ला साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में पहली बार यह कमी हुई है। बाकी वक्ताओं ने भी कमी की बात की। आदरणीय जाधव साहब ने, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। हमारी सरकार निश्चित तौर पर उस दिशा में काम कर रही है।

माननीय उपसभापति जी, मैं यहां पहली बार चुनकर आया हूं। इस देश में रासायनिक खादों के मामले में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता था, गड़बड़ियां होती थीं, उन्हें रोकने के लिए हमारी सरकार ने "नीम कोटेड यूरिया" का चलन शुरू कराया। जिसके चलते क्षरण बंद हुआ, जो भ्रष्टाचार होता था, वह समाप्त हो गया। यही कारण है कि महंगाई को कम करने की दिशा में इन सभी बिन्दुओं पर काम हो रहा है। जहां तक खादों की कीमत में कमी करने की बात है, उसमें कमी हुई है, हमने सिंचाई योजना के लिए किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए, specially 20,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। उन्हें उन क्षेत्रों में, उन प्रदेशों में, इसका अच्छा-सा लाभ मिल सके और किसानों के हित में निर्णय ले सकें, इसके लिए हमने ये सब काम किए हैं।

उपसभापति महोदय, जहां तक हम अपने प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो बताना चाहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ में गरीबी से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने एक रुपये, दो रुपये किलो में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। हम उन्हें फ्री में चावल, नमक दे रहे हैं। आप भी यह कर सकते हैं, बाकी आप जो कुछ भी बोलें, क्योंकि आपको तो यही लगेगा, अच्छे दिन तो दिखेंगे नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पचास सालों में, इस देश के लोगों को अच्छे दिनों का सपना कभी नहीं दिखाया, आप कभी अच्छे दिन लाए नहीं, ...**(व्यवधान)**... लेकिन आज हमारी सरकार ने ईमानदार लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी तरह से काम किया है, इसीलिए अच्छे दिन आ रहे हैं। आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए, जिन्होंने गलत काम किया है, जिनकी भ्रष्टाचार करने में रुचि रही है, अनियमितता मचाकर इस देश के लाखों, करोड़ों रुपये बरबाद किए हैं, ऐसे लोगों के लिए कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री रिपुन बोरा (असम)ः जो 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम हुआ है ...**(व्यवधान)**...

श्री राम विचार नेतामः उपसभापति महोदय, हम महंगाई के बारे में कहना चाहते हैं कि इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। हम कहना चाहेंगे कि आप जहां तक महंगाई के बारे में बात करना चाहते हैं, उसके लिए पहले तो आप यहां पर यह बताइए कि यह महंगाई प्याज में कितनी बढ़ गई? आपने बढ़ा लिया ना। आज मार्किट में प्याज कितनी सस्ती है?

उपसभापति महोदय, महंगाई तो निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन यह महंगाई कहां बढ़ी है? जिस फ़ाइव स्टार होटल में जाते थे, यह महंगाई वहां बढ़ी है। वहां महंगाई इसलिए बढ़ी, क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ाया गया था। आप क्यों जाते हैं? आप वहां जाते थे, इसीलिए महंगाई के बारे में चिंता करते थे। उपसभापति महोदय, दूसरी बात, जिससे महंगाई बढ़ी ...**(व्यवधान)**... महंगाई कहां बढ़ी? महंगाई बढ़ी, क्योंकि वाइन पर, शराब पर बहुत ज्यादा tax लगा दिए गए,

सिगरेट पर ज्यादा tax लगा दिए गए। जो tobacco है, उसका जो उत्पादन होता था, उसमें महंगाई ज्यादा बढ़ी है। यह इसीलिए किया गया ताकि लोग कम से कम लोग उपयोग करें। उससे हतोत्साहित तो हों। उसे बढ़ावा न मिले, उसे कम किया जा सके, इसीलिए ऐसी चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है। अगर आप उसके प्रेमी हैं, तो आपको तो बुरा लगेगा ही। आपको तो लगेगा ही कि उसमें महंगाई कैसे बढ़ गई?

उपसभापति महोदय, यह तो गरीबों की सरकार है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में पहली बार, जब उन्होंने संयुक्त रूप से भाषण दिया था, तो गरीबों के लिए इस बजट को समर्पित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम यह बजट गरीबों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के लिए समर्पित कर रहे हैं और यह बजट उनके लिए है।

उपसभापति महोदय, जहां तक और भी बहुत सारी बातें हैं, हमारी सरकार के द्वारा, हमारे खाद्य मंत्री भारत सरकार, माननीय रामविलास पासवान जी द्वारा, जो आज यहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर, पूरे देश के तमाम राज्यों के लिए, वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की, वहां के खाद्य मंत्रियों से बात की। उन्होंने यहां पर संयुक्त रूप से बैठक बुलाकर उन्हें निर्देशित किया कि वास्तव में जो महंगाई बढ़ रही है, आप उसको अपने प्रदेश में कंट्रोल कीजिए, अपने प्रदेश में छापामारी कीजिए, उनका जो लाइसेंस है, उनकी जो भंडारण की सीमा है, यदि उससे अतिरिक्त भंडारण मिलता है, तो उनके विरुद्ध, उन पर कार्यवाही कीजिए। इस आदेश के बाद तमाम प्रदेशों में कार्रवाइयां हुई हैं, पूरे देश भर में छापे मारे गए हैं। 14,507 का उनका जो उत्तर था, यह 14.7.2016 का उत्तर आया है कि पूरे देश में इतनी छापेमारी हुई है, उसकी वजह से भी जो excess stock मिला है, उस पर भी बहुत कार्यवाही हुई है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे निज़ात पाने के लिए हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जहां तक इसका प्रश्न है कि जो उत्तर उन्होंने दिया है, चाहे काबुली चने की बात हो, चाहे दाल आयात करने में अनुमति देने की बात हो, उसमें भी अनुमति देकर कि हम आयात कर सकते हैं, मैं उस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में बहुत सारी दालें का आयात करके, गरीबों के हित में कुछ न कुछ काम हो, जिससे महंगाई को बढ़ावा न मिले, इसके लिए भी आयात करने के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं।

उपसभापति महोदय, हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जहां तक सब्जियों की बात है, अगर आप अभी ऑफ सीज़न में कहेंगे कि टमाटर क्यों महँगा हो गया, अगर आप कहेंगे कि प्याज क्यों महँगा हो गया, तो स्वाभाविक है कि आज पैदावार नहीं है, तो उसका crisis तो रहेगा ही और महँगाई बढ़ेगी।

उपसभापति महोदय, यहां पर हमारे बहुत सीनियर भूतपूर्व मुख्य मंत्री, माननीय श्री वोरा साहब बैठे हैं। हमारे यहां रायगढ़ जिले में एक ऐसी जगह है, जशपुर जिले में एक ऐसी जगह है, जहां टमाटर के सीज़न में इतना टमाटर होता है कि अगर लोग उसे बिक्री नहीं कर पाते हैं, तो किसान उसे वहीं छोड़ कर चला जाता है। ऐसी स्थिति भी है। इसी प्रकार से आलू की पैदावार के बारे में होता है। जहां तक उत्तर प्रदेश के कानपुर के आप-पास का पूरा एरिया है, इटावा का पूरा एरिया है, इन क्षेत्रों में भी यही हालत है। इसी प्रकार जब हमारे यहां कटहल की पैदावार होती है, तो लोग कटहल को भी छोड़ देते हैं। वे ट्रक से उसको बेचने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अगर उसकी बिक्री नहीं होती है, तो वहीं ट्रक से unload करके उसको छोड़ कर चले

[श्री राम विचार नेताम]

जाते हैं। उपसभापति महोदय, जब ऑफ सीज़न आता है, तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इसलिए ऑफ सीज़न में हमें महँगाई तो दिखाई देगी ही। जहां तक खाद्यान्न की बात है, तो हम यह कह सकते हैं कि खाद्यान्न में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभापति महोदय, सदन में जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम इस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप में न जाएँ और एक सकारात्मक सोच रखें। अगर इस देश में महँगाई बढ़ रही है, तो हम सब मिल-जुल कर उस महँगाई को कैसे कम कर सकते हैं, कहां कमियां रह गई हैं, कहां lapses हैं, उनको दूर करके हम इस देश में एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था बनाएँ और इस देश की जनता को एक बेहतर वातावरण दें, जीने का अधिकार दें। इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने हमारी बात को बहुत ही गंभीरता से सुना और इधर देख कर हमें समर्थन दिया, उससे लगता है कि आपकी मुस्कराहट हमारे मनोबल को और बढ़ाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Sir, this is a discussion on an extremely important issue that concerns the life and death of our people. Recently, my party had organized a nationwide protest action in which lakhs and lakhs of people participated. That generally shows the manner in which people are concerned about the relentless rise in the prices of all essential commodities. The status of that, Sir, according to the answers given in this very House and in the Parliament by the various Ministers is if you just look at the situation of what is the state of affairs, the overall retail inflation is on a 22-month high, at 5.77 per cent. These are the official figures given here. The food inflation is close to 8 per cent. The media is reporting that 'Food is on Fire'. This is the headline. Prices of potatoes have gone up by nearly 65 per cent, pulses by 27 per cent and vegetables by 17 per cent. This is the relentless burden that has been imposed on our people today through this price rise. Hon. Members from the Ruling Benches have laboured to try and ensure that this is also a responsibility of the State Governments. They should crack down on hoarders, black-marketers, etc. That is true. I am not disputing that. That needs to be done. But look at the responsibility of the Central Government in all that is happening. What is price of *dal* today? Between 2014 and 2016, the gram *dal* has gone up by more than double, 100.65 per cent increase; arhar dal has gone up by 100.26 per cent; urad *dal* has gone up by 99.34 per cent. This is the State of affairs as far as the poor, a vast majority of our people are concerned. And this is not due to only black marketing, which, of course, needs to be curbed. There is no doubt about it that State Governments have a role. But that is not the only reason. Why do I say that? Look at the various decisions taken by the Central Government. All of us know hike in fuel charges increases the rate of inflation in an overall manner, and there is an inflationary spiral that is set in motion when fuel prices go up because of transportation costs.

When this Government took office, the international price of crude was 106 dollars per barrel. It came down to 26 dollars per barrel in January, 2016. It is now going slightly up. It is around 40 dollars per barrel now in July. The fall has been from 106 dollars to 26 dollars. But, in this period, what has been the price of diesel? It is ₹ 54.30 per litre when the refinery delivery cost to the petrol pumps is only ₹ 25.10 per litre. That is more than double the cost that is there at the refinery, which is being charged from the public. Petrol price is ₹ 62.56 per litre. I am talking about Delhi. What is the refinery cost at delivery? It is ₹ 22.94 per litre. It is forty rupees more than what is the refinery cost, which is being charged. Why? It is because after this Government came, it has hiked excise duty on petrol and diesel nine times. As a result, people are paying ₹ 40 more per litre for petrol; they are paying nearly ₹ 35 more per litre for diesel and this is causing an overall rate of inflation all across the country. That is purely the Central Government's responsibility. It's not of any one State. The Government is reaping in its own revenue at the expense of the people. This is one instance of fuel charges.

Now, look at the hikes in the cess that the Government has introduced in the last two years. What are the new cesses? It's a long list that has come out. I am reading out for your information and for the information of the august House. New cesses have been imposed. Service tax has been up in the 2015-16 Budget from 12.36 per cent to 14 per cent; Swachch Bharat cess is 0.5 per cent; Krishi Kalyan cess is 0.5 per cent; infrastructure cess on the vehicles is from one to four per cent depending on the type of vehicle; clean environment cess, which was earlier called the clean energy cess, has been doubled. Then, oil development cess. It used to be ₹ 4,500 per tonne, but it has now been increased to 20 per cent *ad valorem*. *Ad valorem* means including the taxes, what the price is. On that, they have 20 per cent oil development cess. Then, secondary and higher education cess, which has been recovered till 2015, is ₹ 64,000 crores. Not one paisa has been spent. All of all has gone into the Governmental revenue. All the cesses put together, if you look at the road cess and all this, which were there earlier, are the extra burden on the people and that is leading up to the rise in prices. Who pays these cesses? It is the consumer. When the consumer pays all these cesses, it only adds to the rate of inflation. Overall, that goes up – whether it is the fuel price or whether it is the cesses. Sir, please remember that cess has nothing to do with the States. In fact, whatever is earned from the cesses is earned directly by the Central Government and not shared with the States at all. So, all this is revenue to the Centre. If inflation is going up today, it is going up because of these measures for which the Central Government and the Central Government alone is responsible. And, therefore, what needs to be done? It is an overall miserable situation. You heard many colleagues

[Shri Sitaram Yechury]
here speak of the rate of growth of unemployment in our country. The hon. Minister for Commerce, who is not here now, has gone on record here and in the other House to say that 1.35 lakh jobs have been created. How many youth join the job market every year? It is 1.3 crore. As against that, we have created 1.3 lakh. It is one per cent of the newly joining employment market youth. What about the backlog? With this level of unemployment and this sort of price rise, it is actually killing the people. This is causing greater and greater misery, and this is happening directly because of the decisions of the Central Government. Yes, the capabilities of State Governments and what they have to do is a separate matter. But, now, I am raising this issue here because of its importance.

As I said earlier, the life and death question for our people seeks that the Central Government takes measures to remedy this, when they are collecting so much of money for augmenting their revenues. There is nine-time increase in excise duty on petroleum products. If you are imposing all these cesses, find a remedy and see what needs to be done for giving relief to the people through direct benefits or whatever they may be. What needs to be done immediately is that we must ban, and this is a point I had raised, you would be familiar with, Sir, a number of times, forward trading and futures trading on all essential commodities. That is absolutely essential because speculation has taken over everything. Earlier, it was rice, wheat, pulses, sugar, potatoes, everything was there in the speculation market. But, we had done and it worked. In the last decade, once, it was done. Essential commodities were kept out of the futures trading commodities exchange and within six months, the prices fell. But we are not learning from that experience. The Central Government has to do that even if it goes against the interests of some traders, some middlemen. But for the interests of the people at large, this is a measure that needs to be done today. It has reached a situation where power is becoming a part of this speculation. You have privatised power transmission. People, who are transmitting power, private transmitters, are not linking up to the grid. They are not linking up to the grid because of speculation on the pricing and because of that the country suffers power shortages. This speculation has to be reined in. If you are serious about controlling inflation and providing some relief to the people, rein in speculation. Ban, at least, for some time or suspend all essential commodities from your commodities exchanges, futures trading and forward trading. That is absolutely essential. The hon. Minister, our old friend and a very experienced, is here. I would like to impress upon him, through you, to, at least, undertake this step and we will see the results in three months, if they actually do this.

The other point, which is also very important for us to consider in this context, is that price rise or inflation – any economist will tell you – is a classic income redistribution measure. Inflation means the income is redistributed from the consumer to the producer, that is, the consumer pays more, the producer should earn more. In Economics theory, they will tell you that this is the classic case in which you want to redistribute income from the poor to the rich. Such redistribution is happening in our country when the economic inequalities are already widening. You have a hundred US-Dollar billionaires in India today. India is shining for them. Those India shining one hundred US-Dollar billionaires, hundred individuals, have an asset value, amongst themselves, between one-third and one-half of our country's GDP. What does our 2011 Census tell us, Sir? In 90 per cent of the families in India, the bread earner earns less than ₹ 10,000 a month. It is 90 per cent. The figures of 2011 Census came out only a few months ago. This is the difference. On top of this, inflation means further widening of this gap, transferring income distribution from the poor to the rich. But in our country, there is an added thing. Classic economic theory would not explain this. It is not the producer who is gaining. It is the people who trade in between who are gaining the most. Take the example of *dals*. We are buying *dal* and we are assuring our farmers a minimum support price of ₹ 50.50 per kg for *dal*. For how much is it selling in the market? At ₹ 120. How much are we paying to import the same *dal* from farmers in foreign countries? At ₹ 152.

We are paying ₹ 152 for imported dal, in the name of saying that we are providing it for our people. To our farmers you give only ₹ 50.50, but, in between, you sell it at ₹ 120. Who is gaining? We are turning economic theory on its head. Here, inflation does not mean, consumer suffers and the producer gains. Here, inflation means, consumer suffers, producer suffers, and the middleman gains. And it is this speculator and the middleman, who is thriving at the expense of these policies, and that has to be curbed. And that is very important if you really want to address this issue of curtailing inflation. Sir, I beseech the Government, through you. You have raised enough resources through all these cesses. You have raised more than enough resources through all these hikes in excise duties, etc. The Governmental revenues are there. You are earning brownie points from international finance, saying that fiscal discipline is there in India, but, at what cost? Fiscal discipline at the cost of our people! Is that the price we pay? Economic development, after all, is not only GDP growth rates. It is the quality of life of our people. And about that quality of life of our people, what does this Government's own Economic Survey tell you?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: When GDP rises, the quality of life should improve. Isn't it?

SHRI SITARAM YECHURY: Not automatic, Sir. Not at all automatic. Not at all. And that is what I am trying to explain. The GDP grows, and we have 100 US-Dollar billionaires. And the GDP grows more, it will be 150 US-Dollar billionaires. From Shining India, you will have a suffering India.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a trickle-down theory.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the law of gravity does not apply in economic theory. Nothing trickles down. If there is anything, it trickles up, and that is the price rise that we are talking about. It defies the law of gravity. ...(*Time Bell rings*)... Sir, I am concluding. If this has to be curtailed, on the one hand, the Government will seriously have to address this question of curbing speculation and ban trading in essential commodities and, on the other hand, stop these cesses, these excise duty hikes, and thereby, provide relief to the people and ensure proper MSP. When agriculture growth goes up by one per cent, your overall GDP grows by more than 0.7 per cent and your industry grows by more than 0.5 per cent. India is a rural, farmer-based economy even today. If you forget that, you are forgetting the essence of what India is and, thereby, these sorts of effects will come.

I am glad that this discussion has been initiated by my colleague from West Bengal, whose State Assembly tried twice to discuss this issue of price rise, but was not allowed by the State Government there. But, anyway, I am glad that it has come up here, and I hope that this message will go there. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much. Now, Shri D. Raja.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. Endorsing the points made by my comrade, Mr. Yechury, I would like to raise a few issues. Sir, this debate should not end as a ritual that we do in every Session or every year. It should lead to a certain real action by the Government to contain inflation and control prices. Sir, it is a fact that prices are increasing. The prices of all commodities are increasing. The prices of food items, essential commodities, have gone up. The price of education has gone up. The price of healthcare has gone up. The price of housing has gone up. The price of medicines has gone up. The prices of all the commodities have gone up. But there is one commodity whose price is not increasing relatively, that is, the commodity of labour power. That is, the wages of the people are not increasing relatively.

Sir, anybody who knows A, B, C of the Economics knows that the price rise is an issue of demand and supply. Price rise is all about how market forces operate for profit making. Price rise is all about competition among the sellers, competition among the buyers, competition between sellers and buyers. But here is the competition

5.00 P.M.

where the price of labour power is not increasing. It is a question of the income of our people that is not growing. The purchasing capacity of our people is not growing. The other name for the price rise is low income. The other name for the price rise is low wages. I am asking the Minister: How is the Government going to address the issue?

Sir, India has started as a welfare State immediately after Independence. I raised this issue on many occasions. Again, I am reminding the House. Today, the Indian State is transforming itself into a neo-liberal State. You are concerned with the profit of big business houses and corporate houses. You are not that concerned with the interest of the people. People are suffering. Those who live in cities, those who live in villages, they all suffer. That is what the Government should understand. I think there is a need for effective intervention of the State, when I say of the State, it is the Government. I know that there are some State Governments, for instance, the Government of Kerala and the State Government of Tamil Nadu who do intervene in the situation to control prices, to ensure the supply of food items at affordable prices to our poor people. Now, what is happening? We have been demanding that the Public Distribution System (PDS) should be strengthened and streamlined. In fact, we have demanded universalisation of the Public Distribution System. In that context we have also demanded banning of Future Trade. The Government is yet to discuss these issues seriously.

We had enacted the National Food Security Act, and I am asking the Government: Are you implementing the Act? Under that Act, are you ensuring the food items, essential commoidities to our poor people at affordable prices? I am asking you straightaway whether the Government is sincere in implementing the Natioinal Food Security Act. Sir, now it is linked with the Aadhaar Card. Why do you link it with the Aadhaar Card? You allow people to have access to the Public Distribution System with their ration cards. There are several ration cards. Why do you link it with the Aadhaar Card and deny the poor people access to the Public Distribution System?

Sir, now they have introduced one more idea. It is there on a pilot basis in many States. The so-called POS. Do you know, Sir, what POS stands for? It is Point of Sale. Even I am not very clear. What is that POS? But it has been introduced on a pilot basis in several States. There people will have to go and give biometric impression. If it doesn't match, people are denied. On the one side, you talk about the National Food Security Act and on the other side, you deny the access to the Public Distribution System to a large section of our people. What is happening in our country? What is happening with the Central Government? I am asking you.

[Shri D. Raja]

It should be the task of the Government to ensure the implementation of our own Act, this Parliament had passed the National Food Security Act.

Regarding drought, even the Supreme Court has commented that the Government should ensure the NREGA and the Minimum Wages Act in all the drought-affected areas. Forget drought-affected areas. The question is whether the Government is seriously implementing the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act and the Schemes under that Act. Sir, the Act carries the name of Mahatma Gandhi. Let us be sincere to Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fought for our children and the *daridranarains* of this country. The Scheme carries his name. But you are not giving sufficient funds for the NREGA. You are not giving sufficient funds and you are not asking the State Governments to implement that Scheme sincerely. So, these are all the issues. And, as Comrade Yechury has said, there are larger issues and short-term issues but, as the Government, you can intervene. The question is: why are you not intervening? Why are you not implementing these Schemes? You have been talking about inflation. Inflation is high. Everybody knows about it. I can reel out the figures, the figures given by your Government. The price of crude oil has gone down in the international market. Even the pump price of petrol fell by 17 per cent in India. The Indian crude basket fell by 72 per cent. But it has not been transferred to our consumers. So, price rise is an issue. ...(*Time-bell rings*)... And this issue has to be addressed on a priority basis. The Government talking about 'good days' has no meaning. Even before the last Lok Sabha elections that was the issue and you were accusing this Party for failing in controlling the prices and in containing the inflation. Now, it is two years since you came to power; what have you done? That is my question. Are you competent enough and are you in a position to control the price rise and contain inflation? ...(*Time-bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

SHRI D. RAJA: So, in the interest of the poor people, I make an appeal to the Government. There are unemployment and other issues. We would discuss them. ...(*Time-bell rings*)... Just a second, Sir. I am finishing.

The point is that even the RBI Governor has said this. Now, you may have thousands of opinions about the RBI Governor. I have my own opinion about him. But it is the RBI Governor who had once said that for wiping out the tears of every Indian, our per capita income will have to rise to 6,000 US dollars. ...(*Time-bell rings*)... I am asking you when it would be possible.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. Sit down now.

SHRI D. RAJA: I would like to ask whether the Government has any vision of how to increase the per capita income of our people, increase the wages of our people and increase the income of our people. Until such a visionary approach is there, the Government is bound to fail.

Thank you, Sir.

SHRI SITARAM YECHURY: To correct my Comrade, the Mahatma had said, "Wipe every tear from every eye.'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Gandhiji had said that. Now, Shri Narendra Budania.

श्री नरेंद्र बुढानियाः महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महोदय, आज हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं जो आम व्यक्ति से, इस देश के गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे बहुत तकलीफ है यह कहते हुए कि मैं पिछले तीन घंटे से इस बहस को सुन रहा हूं और मुझे यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस गंभीर मुद्दे को जो सब को मिलजुल करके इसका मुकाबला करना चाहिए, उस बात को नहीं रखकर यहां पर एक दूसरे की सरकारों पर इस प्रकार का ब्लेम डाल रहे हैं। विशेष तौर पर मुझे तकलीफ इस बात की है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग कोई अच्छा सुझाव देने के बजाए, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, इस प्रकार की बात करने में ज्यादा जोर रख रहे हैं। मैं पिछले 10 साल की बात गिनाने लगूंगा तो मैं समझता हूं कि कितने घंटे मुझे लग जाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले ढाई साल में आपने क्या किया? आपने ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे गरीब का भला हो? जो गरीब के लिए खाने की वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनका मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए आपने कौन से कदम उठाए, यह मैं जानना चाहता हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष खाद्य वस्तुओं की जो कीमतों हैं, वे 62 प्रतिशत बढ़ी हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों 25 प्रतिशत बढ़ी हैं। महोदय, पिछले ढाई साल से, जब भी बहस हुई है, मैं यह सुनता आ रहा हूँ कि हम दाल की कीमतों के ऊपर कंट्रोल करेंगे, हम सब्जियों और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के ऊपर कंट्रोल करेंगे। इसके लिए कार्रवाई करने की बात यहां कही जाती रही है। यहां पर जोर-शोर से कहा गया कि हम कालाबाजारियों एवं जमाखारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएँगे। सदन ने आप पर विश्वास किया, पूरे देश ने आप पर विश्वास किया, लेकिन क्या हुआ, आपने उसमें क्या किया? आपने जमाखारों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये जमाखोर सरकार के अंदर पैठ रखते हैं। आपमें हिम्मत नहीं है कि आप इन जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें।

महोदय, गरीब व्यक्ति के लिए दाल और सब्जी बहुत दूर की बात हो गई है, आज गरीब इनके लिए सोच भी नहीं सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि देश में दाल की कमी नहीं है। हमारी माँग 20 मीट्रिक टन की है और हमारी उपलब्धता 21 मीट्रिक टन की है, जो कि दस लाख टन

[श्री नरेंद्र बुढानिया]
अधिक है, लेकिन फिर भी दाल के दाम कम क्यों नहीं हुए? दाल के दाम इसलिए कम नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने इन व्यापारियों को* मचाने की पूरी छूट दे रखी है।

महोदय, मैं पिछले दिनों एक सवाल का उत्तर पढ़ रहा था, उसमें कुछ प्रदेशों के नाम दिए गए थे। मुझे बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं राजस्थान से चुन कर आया हूँ और राजस्थान के आस-पास के स्टेट्स, जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश में उसके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिए जाते हैं, कोई बात नहीं बताई जाती है। यह क्यों नहीं बताया जाता है कि वहां पर कितने छापे मारे गए, कितने जमाखोरों को पकड़ा गया, कितने लोगों को जेल में डाला गया और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया? महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन चार प्रदेशों के अंदर कितनी तेजी से इन सब चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। अगर मैं चने की दाल की बात करूं, तो हरियाणा में पिछले साल, यानी 14.7.2015 को इसकी कीमत 4,825 रुपए क्विंटल थी, जो बढ़कर 8,900 रुपए प्रति क्विंटल हो गयी। पंजाब में यह 5,100 रुपए प्रति क्विटल थी, जो बढ़कर 8,767 रुपए प्रति क्विंटल हो गयी। मध्य प्रदेश में पिछले साल यह 4,675 रुपए प्रति क्विंटल थी और इस सप्ताह वहां पर इसकी कीमत 7,917 रुपए प्रति क्विंटल है। मंत्री जी, आप सुन रहे हैं, आप राजस्थान से चुन कर आए हैं और मंत्री बने हैं। आपको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप राजस्थान की तरफ ध्यान देंगे, जनता आपसे ऐसी उम्मीद करती है। राजस्थान में जुलाई, 2015 में इसकी कीमत 4,800 रुपए प्रति क्विंटल थी और जुलाई, 2016 में यह 7,233 रुपए प्रति क्विंटल है। महोदय, किस प्रकार से भाव बढ़ रहे हैं? मैंने तो यह चने की दाल की बात बताई है। मैंने यह थोक भाव बताया है। अब आप इसका रिटेल भाव सुन लीजिए। चने की दाल का रिटेल भाव हरियाणा में पिछले साल 52 रुपए प्रति किलो था, जो अभी 95 रुपए प्रति किलो है। इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? पंजाब में पिछले वर्ष इसका भाव 56 रुपए प्रति किलो था, जो अब 95 रुपए प्रति किलो है। मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष इसका भाव 49 रुपए प्रति किलो था, जो अब 83 रुपए प्रति किलो है। राजस्थान में पिछले वर्ष इसका भाव 51 रुपए प्रति किलो था और अभी यह 78.30 रुपए प्रति किलो है। देखिए, इसके भाव कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। आप चाहेंगे, तो मैं सभी दालों के बारे में बता सकता हूँ कि किस प्रकार से इनके भाव बढ़े हैं। आप दोनों मंत्री एक ऐसे वर्ग से आते हैं, जो इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आपको मालूम है कि ये भाव क्यों बढ़ रहे हैं? आपको मालूम है कि इन भावों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप दबे हुए हैं। आप उन बड़े लोगों से दबे हुए हैं, जो बड़े व्यापारियों से लाभ ले रहे हैं। आप कार्यवाही करने से झिझक रहे हैं। आप कार्यवाही करते हैं तो आपके ऊपर बैन लगता है, ऐसा हमें नज़र आता है। ...**(व्यवधान)**... ...(*Time Bell rings*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Budaniaji, please conclude.

श्री नरेंद्र बुढानिया: मैं कुछ और बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। महोदय, अभी तो मैंने वे चार स्टेट्स बतायी हैं, जिनमें बीजेपी का राज है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I agree. मैं आपसे पूरा सहमत हूं कि यह बहुत important है, लेकिन आपकी पार्टी ने 9 नाम दिए हैं। मैं क्या करूं?

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, बस हो गया। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें इन खाद्य वस्तुओं के भावों को नियंत्रित करना है तो हमें किसान की मदद करनी होगी। अगर हम किसान की मदद नहीं करेंगे तो हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते, इसलिए किसान को सब्सिडी दीजिए, उसे खाद उपलब्ध कराइए, खाद सस्ते भाव पर उपलब्ध कराइए, खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराइए। मेरे पास सारे प्रदेशों के आंकड़े हैं। आपकी मांग कितनी है और उपलब्धता कितनी है, आपकी सेल कितनी है। आप इसका difference देखेंगे तो चौंक जाएंगे। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापतिः अच्छा अब आप बैठिए। Okay, ठीक है, बस अब हो गया।

श्री नरेंद्र बुढानियाः लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हमारे ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. अब बस करिए।

श्री नरेंद्र बुढानियाः महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं एक नयी बात बताना चाहता हूं।

श्री उपसभापतिः सब नयी बात ही है।

श्री नरेंद्र बुढानियाः हम जो दाल आयात करते हैं, वह बहुत महंगे भाव पर करते हैं। पिछले वर्ष जब आप उपसभापति थे और जब मैं इस साइड में बैठा था, तो मैंने EXIM Bank पर बोलते हुए कहा था कि आप आयात और निर्यात के लिए दस हज़ार करोड़ रुपए EXIM Bank को दे रहे हैं और महंगे भाव पर खरीद रहे हैं। आप क्यों नहीं किसानों को सब्सिडी देते, क्यों नहीं उन्हें उत्साहित करते, ताकि वे भाव बढ़ाए। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, please. Okay now. That is all. You have taken 9 minutes.

श्री नरेंद्र बुढानियाः महोदय, आज हम दालों को म्यांमार, कनाडा और अफ्रीका से खरीदते हैं। मैं नॉर्थ-ईस्ट के बारे में बताना चाहता हूं। नॉर्थ-ईस्ट म्यांमार से जुड़ा हुआ है। चाहे वह मणिपुर हो, चाहे मिज़ोरम हो, आज मिज़ोरम में हम लोग इतनी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. Shri R. S. Bharathi. ...(*Time Bell rings*)... Now, Shri R. S. Bharathi.

श्री नरेंद्र बुढानियाः जो वहां की जलवायु है, उसमें हम उनको मदद देकर दाल की पैदावार बढ़ा सकते हैं और गरीब की मदद कर सकते हैं।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH : He has finished. He has already spoken.

श्री उपसभापतिः ठीक है। Then, Shri Ripun Bora.

श्री नरेंद्र बुढानियाः इन्हीं बातों के साथ, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 15 मिलियन हेक्टेयर फेलो लैंड तथा साढ़े 12 मिलियन हेक्टयर खेती के लायक वेस्ट लैंड पड़ी है। इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनकी पैदावार बढ़ानी चाहिए, तभी किसान आपका होगा, नहीं तो जनता आपको कभी माफ करने वाली नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Yes, Sir. I am on my legs.

श्री नरेंद्र बुढानिया: ढाई साल का समय चला गया है और ढाई साल का बचा है, किसान आपके बारे में इतना सोच रहा है और आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते।

श्री उपसभापति: रिपुन जी, आपके पास पांच मिनट हैं because your party time is over. Now, Shri Ripun Bora.

SHRI RIPUN BORA: Thank you, Sir. I am the lone speaker from the North-Eastern State. From the eight States of the North-East, I am the lone speaker. Sir, we have been keenly discussing this very, very important national issue for the last three hours. I want my BJP friends to recall one of their popular slogans in the year 2014, which many of my friends have also cited, that is, 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।' So, the Modi Government came in 2014. But, after the coming into power of the Modi Government in 2014 — we are in 2016 — in these two years, how the prices have gone up! I just want to cite examples of two items. That is, during our UPA Government, the prices of all items of pulses were on an average ₹ 65/- to ₹ 75/- per kg. Now, these have gone to ₹ 180/- to ₹ 200/- per kg. In our State, Assam, it is much more than that. I am citing examples of only two items. Similarly, in the case of mustard oil, during the UPA regime, its prices were ₹ 60/- to ₹ 75/- per litre, on an average. Now, it has gone up to ₹ 150/- to ₹ 180/- per litre and it varies from State to State. This is one thing. Sir, the second thing is this. The House will be surprised to know that only in one month, *i.e.*, in the month of May — I am not speaking about the two years of this Government — the inflation rate of food prices was 6.40 per cent; and now in the month of June, it is 7.55 per cent. It is horrible. Similarly, the inflation rate of vegetable prices — here also I am speaking about the month of May — increased from 12.90 per cent to 16.90 per cent; and in the case of fruits, it increased from 3.8 per cent to 6 per cent. This was the increase in just one month. Sir, this is the picture of how the prices have gone up after coming into power of the Modi Government, though they said that they would bring down the prices to half; that was there during the UPA Government.

Sir, price-rise is an issue which is inter-related with various Departments. If the Government takes any wrong policy decision in one Department, it has an impact on the prices. Many of my friends have rightly mentioned this thing. My two friends from the BJP, namely, Shri Prabhat Jha and Shri Malik have quoted the Budget Speech of the Union Finance Minister for the year 2015-16. The Budget Speech was very fine. In the Budget Speech, the hon. Finance Minister has expressed his concern on price-rise. But in the Budget, they have not mentioned how to check it.

By increasing the railway freights and fares, they have broken the record of India after Independence. So, this has an impact on prices.

Similarly, Shri Yechury and other friends also mentioned about the Service Tax and the Swachh Bharat Tax. As regards Swachh Bharat Tax, I want to supplement my friends that by simply raising taxes on public, we cannot get Swachh Bharat. The Swachh Bharat must come from our heart; our heart must be swachh. Unless our heart becomes swachh, we cannot stop the atrocities on women, we cannot stop the atrocities on Dalits and we cannot stop the atrocities on minorities and Muslims.

Sir, one of the wrong policy decisions was this. There are so many factors for price-rise, but the main two factors are: One is exports and the other is hike in the cost of production. Sir, in the last Session, we had a long discussion on drought in the country; and now our country, including Assam, is facing a severe threat of floods. There are severe floods in various States of the country. Sir, this Government has not taken effective steps for combating the drought situation as well as the flood situation. As a result, what happened is this. The agricultural production has come down; and on the other hand, the cost of production has increased. ...(*Time-bell rings*)... But the Government has not taken any steps in this regard. Sir, please give me just one minute. The Government has not taken steps to increase the purchasing power of the people. In order to combat the skyrocketing prices, the Government should take the initiative for increasing the purchasing power of the people. But they are going to increase the purchasing power of whom? They are going to increase the purchasing power of the big businessmen and the corporate sector. In the last year's Budget, they have lowered the Income-tax from 30 per cent to 25 per cent for the corporate sector, and thereby they have given them a remission of ₹ 5.50 lakh crores at the cost of the poor people. So, they have increased the purchasing power of the big businessmen and the corporate sector, but not of the poor people.

Sir, I would like to remind my friends that during the regime of the UPA Government, when there was a rise in petrol prices, they protested all over the country. For their protest modes, they used bullock carts, they used horse carts and they used bicycles. When onion price rise was there, they made garlands of onions. Now, I would like to ask my friends: Where has that spirit gone? Now, the fuel prices have not come down. Have they come down? Why are you not protesting? Prices of pulses have gone up to ₹ 200/-

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RIPUN BORA: Will my friends take the cause of rise in prices of *dal*? With these few words, I suggest to the Government to ensure effective implementation of food security, envisaged by the UPA Government, and the effective implementation of the Public Distribution System. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Husain Dalwai, please take only five minutes.

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, जब यूपीए सरकार थी, तब दाल के दाम 70 रुपए किलो तक हो गए थे। उस समय बड़ा हंगामा हुआ। इस सदन में हर रोज बड़ा हंगामा होता था कि दाल कितनी महंगी हो गई है। हर दिन वही बात चलती थी। आज दाल के दाम 200 रुपए प्रति किलो हो गए हैं, फिर सरकार चुप क्यों है? पासवान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप डॉ. लोहिया को मानने वाले हैं। डॉ. लोहिया ने 'दाम मांगो नीति' दी थी। आज यह आपके हाथ में है, अगर है, तो क्योंकि सारा कुछ तो PMO के हाथ में रहता है। मुझे पता नहीं है कि आपके हाथ में क्या है, लेकिन अगर है, तो आप वह दाम मांगो नीति लाइए, तब कुछ सुधार होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही यूपीए सरकार के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हुईं। यहां इनिशिएट करते हुए एक ऑनरेबल मेम्बर बोले कि आपके जमाने में क्या हुआ, यह हुआ, वह हुआ। इसके पहले के बारे में बताने के बजाए, अभी क्या हो रहा है, उस पर विचार करना चाहिए। अभी आपके हाथ में सरकार आई है और फुल मेजॉरिटी भी मिल गई है, तो आप क्या-क्या करेंगे? आपने दो साल में केवल यही काम किया है कि महंगाई की 3 गुना बढ़ोतरी हो गई है। दाल के भाव 3 गुना बढ़े और अनाज के भाव भी बढ़ गए हैं। सातवां वेतन आयोग आया है, तो मुझे कुछ कर्मचारी बोले कि हमारा यह सातवां वेतन आयोग का पैसा, तो दाल खरीदने में ही चला जाएगा। इस तरह से कुछ भी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आपने आस्ट्रेलिया से दाल मंगाई। हमारे एक मित्र की बीवी ने फोन करके बताया कि यह दाल गलती ही नहीं है। इस दाल को पकाना बड़ा मुश्किल होता है। यह दाल खाने लायक भी नहीं है। उस दाल में इतनी बदबू आती है कि घर के लोग यहां-वहां चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे कुछ गौरक्षक भी बोले कि यह दाल गाय भी नहीं खाती है। आप यह दाल क्यों लाए, मुझे मालूम नहीं है? आपने लोगों के निवाले से दाल भी निकाल ली और मटन भी निकाल लिया, तो फिर लोगों को प्रोटीन कहां से मिलेगा? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं गौरक्षक हूं। मैं यह नहीं कहता कि गाय कत्ल होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन आप हर जानवर के बारे में बोलने लगे। गरीब आदमी जो हर रोज खाता है, सरकार इन गरीबों के खिलाफ क्यों करती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यूपीए के जमाने में 'राइट टू फूड पॉलिसी' आई थी। उस वक्त हमारे साहब भी थे, वे बड़ी तारीफ करते थे। आज भी सस्ता गेहूं और चावल PDS की दुकान पर ही मिलता है, इसलिए आप दाल भी वहां पर दीजिए। हो सकता है आप कुछ न कुछ थोड़ा बदलाव लाएंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ अच्छी बातें हो जाएंगी।

मैं आपको दो बातें बताता हूं कि आपने मोजाम्बिक में कुछ जमीन आदि लेकर कुछ करार वगैरह किया है और उसके जरिए आप वहां दाल तैयार करने वाले हैं। उसका क्या हुआ, क्या उस करार का कुछ हो रहा है? अरुण जेटली साहब की एक कमेटी आ गई है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी हैं, पासवान जी, आप खुद हैं और राधा मोहन सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी हैं। उसका क्या हुआ और क्या उसमें कुछ निर्णय लिया है?

मुझे लगता है, आप हमें इस की मालूमात देंगे। आपने 2 लाख का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है। अभी इस पर बात चली तो आपने कहा कि इसे 8 लाख टन करेंगे और अब 20 लाख टन की भी बात हो रही है। आज दलहन और तिलहन का क्षेत्र वही है, फिर इतने बड़े पैमाने पर आप दाल कहां से लाएंगे, हमें इस की भी जानकारी दीजिए। आपने अपने स्टॉक में से 20 लाख टन खुला किया है और राज्य सरकारों को कहा कि ये दाल आप लोगों तक लेकर जाओ।

आज मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, आप वहां बेन को कहिए कि कुछ-न-कुछ करें। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन वे उस दाल को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हमारी सरकार थी और पासवान जी हमारे साथ बैठते थे, तब ये हमें कहते थे कि राज्यों में हमें यह कार्य करना चाहिए। उस वक्त जो 20 हजार टन अनाज दिया गया, वह कहां गया? आपने ई.डी., आई.बी., स्टेट पुलिस, सब कुछ लगायीं, लेकिन फिर भी नियंत्रण नहीं आया। यह क्यों हो रहा है, इसे हम लोग जानना चाहते हैं? मेरे ख्याल से आपने किसानों की सब्सिडी बंद की और आप हर तरह से किसानों को तकलीफ दे रहे हैं। आज दवा के दाम बहुत बढ़ गए हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं रह गया है। लोगों ने प्रोटीन खाना ही बंद कर दिया है। महंगाई के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गयी है, कारखाने बंद हो गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Husain Dalwai, please conclude. These are all repetitions.

श्री हुसैन दलवई: आप तो टीचर रहे हैं ..**(व्यवधान)**... आज स्कूल फीस भी बढ़ गयी है। आपने जो आश्वासन दिए, उन्हें पूरा करें। आप कृपा कर के लोगों के मुंह से निवाला निकालने का काम मत करिए। आपको 2019 तक किसी-न-किसी तरह रहना है, उस के बाद लोग आपको इन बातों का जवाब देंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति: डा. संजय सिंह। प्लीज 5 मिनट में खत्म करें।

डा. संजय सिंह (असम): उपसभापति जी, महंगाई पर चर्चा हो रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे Treasury Benches से और हरेक पार्टी के सदस्यों ने चर्चा की है। Treasury Benches से हमारे साथियों ने प्रधान मंत्री जी का काफी गुणगान किया और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन इस के बावजूद महंगाई पर चर्चा हो रही है। हमारे साथियों ने कहा कि इस समय सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उन कदमों के उठाए जाने के बावजूद हम महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, गेहूं के, दाल के, तेल के दाम पहले क्या थे और आज क्या हैं, इस पर बहुत से फिगर्स के साथ लोगों ने चर्चा की है। अच्छे दिन की चर्चा हुई, लेकिन अच्छे दिनों को बेचकर हम आज इस मुकाम पर हैं कि महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुत से वायदे किए कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे और नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ऐसी कोई खास चीज दिखती नहीं है। आज अच्छे दिन आ गए हैं और विजय माल्या हजारों करोड़ लेकर इंग्लैंड में बैठे हैं और किसानों का ऋण भी माफ नहीं हुआ। न मन की बात हुई और न कोई और बात हुई, हां उद्योगपतियों के सैकड़ों करोड़ जरूर माफ हो गए।

महोदय, जहां तक महंगाई का सवाल है, अगर आप केवल किसानों का हाल देखें, तो सब से महत्वपूर्ण चीज यह है कि खेत-खलिहान में जो चीज पैदा होती है, वह सस्ती होती है, लेकिन चूल्हे तक जाते-जाते सब चीज महंगी हो जाती है। आलू किलो में सस्ता होता है, वह तीन-चार टुकड़ों में जब पैकट में जाता है तो महंगा हो जाता है। मटर खेत में सस्ती, लेकिन पैकट और बोतल में महंगी हो जाती है। दूध महंगा है, बच्चों का पौष्टिक आहार महंगा है। इस तरह हर चीज महंगी है। महोदय, मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सरकार गंभीरतापूर्वक इस बारे में कुछ करना चाहती है, तो वह कोई ठोस कदम उठाए। फिर जीडीपी का गोरखधंधा चलता है, जीडीपी ऊपर जाता रहता है, लेकिन उसका किचन से कोई तालमेल नहीं होता है।

[डा. संजय सिंह]

आज किसान हर चीज़ में परेशान है। वह किस तरह से आत्महत्या कर रहा है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़े समय में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी खराब चीज़ है, वह यह है कि किसान, जो थोड़ी खेती करता है, उसको समय पर बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सही दाम नहीं मिलता। वह बड़ी मुश्किलात के बाद, किसी तरह से खेत में अपना अनाज पैदा करता है, लेकिन जब क्रय केंद्र पर जाता है, तो उसको तीन दिन तक लटकाया जाता है, उसकी फसल की कभी खरीद नहीं होती, लेकिन बीच का आढ़ती सबसे ज्यादा मजे ले रहा है। वह जाड़े में, गर्मी में, बरसात में मेहनत करता है, लेकिन उसकी जो कीमत उसको मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। लेकिन जो कुछ भी नहीं करता है, वो अपनी दुकान में बैठकर सारा फायदा उठा रहा है। यह सरकार आज कम से कम उनके लिए इतना तो कर दे, क्योंकि हमारे उस किसान के पास कोई सूचना भी नहीं होती है कि उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट की मार्किट में इस समय क्या रेट्स हैं, प्रदेश में क्या रेट्स हैं, या राष्ट्रीय मार्किट में क्या हाल है। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने लखनऊ में — लखनऊ में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, उस समय यह तय हुआ था कि उसका इंफ्रास्ट्रचर होगा, उसमें cold storages बनेंगे, एयरपोर्ट पर उसकी सारी व्यवस्था होगी, वह एक्सपोर्ट कर सकेगा, लेकिन आज तक एक कदम भी न तो उस समय की एनडीए की सरकार आगे बढ़ी, न आज की एनडीए सरकार बढ़ रही है। दो, सवा दो साल हो गए हैं, लेकिन आप किसी एक भी ठोस कदम के बारे में बता दें कि आपने आज तक खेती के लिए, उसके उत्पादन के लिए, गरीब किसान के लिए, गरीब मजदूर के लिए कोई चीज़ की हो? उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जब हम अच्छी बात हो रही है और तमाम सारे सपने बेचने की बात करते हैं, तो कोई एक concrete कदम होना चाहिए, जिससे महंगाई को आगे बढ़ने से रोका जा सके।

एजुकेशन को लें, तो जो हमारी मंत्री जी थीं, वे आमूलचूल परिवर्तन नीति करते-करते खुद ही बदल गईं। आज शिक्षा का हाल क्या है, आज इंजीनियरिंग कॉलेजेज में क्या हो रहा है, मेडिकल कॉलेज़ेज में क्या हो रहा है, युनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, आईआईटीज़ में क्या हो रहा है? आप इन सारी चीज़ों के हालात देखने के लिए सोचें।

हमारे उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ बेरोज़गार ग्रेजुएट्स हैं। आज उनके पास रोज़गार नहीं है। इन सारी चीज़ों पर महंगाई का असर पड़ता है। यह सही है कि आज हर चीज़ महंगी हो रही है और किसान, जो अन्नदाता है, उसकी हर चीज़ सस्ती है। ये जो चीज़ें हैं, जब तक इन पर कंट्रोल नहीं होगा, जब तक सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी, तक तक समाधान नहीं होगा।

उपसभापति जी, खेती से लेकर किचन तक, चूल्हे तक जो गैप है, यह गैप जब तक बरकरार रहेगा, तब तक महंगाई भी ऐसे ही रहेगी, तब तक हालात भी यही रहेंगे। आज तमाम तरह की मेडिकल सर्विसेज़ महंगी हैं, आपका कोई सदस्य बीमार है, आपके मां-बाप बीमार होते हैं, तो आपको अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, वेंटीलेटर का धंधा चल रहा है। ...**(समय की घंटी)**... जब तक ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. It is okay ...(*Interruptions*)... It is okay.

डा. संजय सिंहः तब तक न महंगाई पर कंट्रोल होगा, न किसान की स्थिति बदलेगी, न

गरीबी हटेगी और न ही ये सारी तमाम चीज़ें होगी। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि, "कोई लौटा दे, मेरे बीते हुए दिन" अच्छे दिन तो आते रहते हैं और ऐसे आते ही रहेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन वैसी ही रहेगी। माननीय महोदय, मैं चाहता हूं कि आपकी मिनिस्ट्री, वह चाहे पीडीएस मिनिस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री हो, ये जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल करने की, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगी, तब तक हम महंगाई पर ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे ही मौका आएगा और हम सदन में इस पर चर्चा करते रहेंगे।

श्री उपसभापतिः ओ. के. मंत्री जी, आपका रिप्लाई।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः उपसभापति जी, नहीं। मैं दो मिनट के लिए बोलना चाहती हूं। ...**(व्यवधान)**... मेरा नाम है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः नाम है? ..**(व्यवधान)**..

श्रीमती विप्लव ठाकुरः माननीय उपसभापति जी, ...**(व्यवधान)**... मुझे मालूम है ...**(व्यवधान)**... नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मेरा लास्ट है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Viplovji, you also listen to me. Your party has taken sixteen minutes extra ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. Sit down ...(*Interruptions*)... Suppose, you give all fifty names, what do I do?

श्रीमती विप्लव ठाकुरः उपसभापति जी, मैं बीच में इसलिए खड़ी हुई हूं, क्योंकि पुरानी बातों को मत दोहराइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I cannot concede to this. ...(*Interruptions*)... No, no. Sit down. We cannot function this way. ...(*Interruptions*)... Sit down.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप बार-बार मत कहिए कि यूपीए सरकार ने क्या किया ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen to me. You gave nine names. If you give fifty names, am I to allow all? No.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः मैं इसलिए बीच में कहना चाहती हूं कि आप पुरानी बातों को मत दोहराइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Viplovji, this is enforcing ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप बार-बार मत कहिए कि यूपीए सरकार ने क्या किया, ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You cannot do like this ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः यूपीए सरकार ने क्या नहीं किया। ..**(व्यवधान)**..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am only objecting to the principle. ...(*Interruptions*)... My objections is ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप यह मत कहिए कि यह यूपीए सरकार थी, ...**(व्यवधान)**... जब लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is Vioplov. What can we do? ...(*Interruptions*)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आज आप सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे prices कम कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... दोषारोपण से कुछ नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I am being defeated by woman power.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः घर की औरत से पूछिए कि वह किस तरह से काम करती है। कृष्णा जी यहां पर बैठी हुई हैं, आप इनसे पूछिए कि घर कैसे चलता है। ...**(व्यवधान)**... कैसी महँगाई हो गई है, ...**(व्यवधान)**... जब वे सब्जी लेने जाती हैं, तो क्या होता है, ...**(व्यवधान)**... यह आप अपने-अपने घर जाकर पूछिए। आप केवल यह मत कहिए कि उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आज हम रो रहे हैं। आज हमें आधा किलो मटर लेने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, टमाटर-प्याज की तो बात ही छोड़िए। फिर कहते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया। विदेशों में घूमने से चीजें सस्ती नहीं हैंगी। ...**(व्यवधान)**... यहां रहना पड़ेगा, यहां की असलियत से जूझना पड़ेगा, उसे face करना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... बाहर से कोई पैसा देने वाला नहीं है और न तो FDI आएगा। आप महँगाई को काबू करिए, नहीं तो जनता आपको काबू कर लेगी, यही मैं कहना चाहती हूँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान)ः उपसभापति जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनमें देरेक ओब्राईन साहब, — हमारे बहुत ही अच्छे, पुराने मित्र, बहुत सारे साथी हमारे मित्र ही रहे हैं — रजनी पाटिल जी, प्रभात झा जी, नरेश अग्रवाल जी, बालासुब्रमण्यम जी, हरिवंश जी, दिलीप कुमार तिर्की जी, डा. नरेंद्र जाधव जी, आर. एस. भारती जी, प्रमोद तिवारी जी, श्वेत मलिक जी, अशोक सिद्धार्थ जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सरदार बलविंदर सिंह भंडर जी, राजीव शुक्ल जी, राम विचार नेताम जी, सीताराम येचुरी जी, डी. राजा जी, नरेंद्र बुढानिया जी, रिपुन बोरा जी, हुसैन दलवई जी, डा. संजय सिंह जी हैं। ...**(व्यवधान)**... विप्लव ठाकुर जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने गलती की, आपने उनको बाद में बोलने के लिए कहा, उनको पहले बोलने के लिए कहना चाहिए था। ...**(व्यवधान)**... मैं आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

उपसभापति जी, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि सिर्फ discussion के लिए ही यह discussion नहीं होना चाहिए और हर साल discussions होते हैं, उनमें से कोई concrete बात भी आनी चाहिए और इस पर निर्णय भी लेना चाहिए। मैं बहुत गौर से सब साथियों की बातें सुन रहा था। ओब्राईन जी ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए, सब साथियों ने अच्छे -अच्छे सुझाव दिए। सीताराम येचुरी जी ने forward trading के सम्बन्ध में कहा कि दाल के ऊपर forward trading नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। फारवर्ड ट्रेनिंग दाल के ऊपर नहीं है। यह चना के ऊपर था, लेकिन हमने उसे बंद करने का काम किया। हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी साथी यहां नहीं बोल पाए हैं, आप हमें सुझाव दीजिए। हम मंगलवार को हमेशा यहां उपलब्ध रहते हैं। आप जब कहें, हम आपको बुला लेंगे। हम लोग चाय पर बैठ जाएँ और जो भी सुझाव होगा, ...**(व्यवधान)**... आपका जो भी सुझाव आएगा, हम उसको गम्भीरता से लेने का काम करेंगे।

उपसभापति जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि यहां कहा गया है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सारे आँकड़े हैं। यदि आप उन आँकड़ों को देखेंगे, तो उन आकड़ों के मुताबिक, हम overall नहीं कहेंगे, क्योंकि Finance Ministry की ओर से कुछ होगा, तो वे कहेंगे, लेकिन जहां तक महँगाई का सवाल है, महँगाई overall 2012-13 में 10.2 परसेंट थी, जो जून, 2016 में घट कर 5.8 परसेंट हो गई है। जहां तक दाल का सवाल है, जितनी चीजों के भी दाम हैं, अगर आप चावल को देखेंगे, तो एक साल पहले यह 27 रुपए 66 पैसे था और 25.7.2016 में यह 27 रुपए 5 पैसे है। 14.7.2015 को गेहूँ 22 रुपए 88 पैसे था और आज यह 22 रुपए 67 पैसे है। वनस्पति तेल 74 रुपए 75 पैसे था और आज 74 रुपए 4 पैसे है। सोयाबीन ऑयल 82.23 रुपये था, अब 82.72 रुपये है ...**(व्यवधान)**... आप जरा सा सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... कम से कम रिकॉर्ड में भी तो आने दीजिए, हम आपकी बात पर भी आ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सनफ्लॉवर ऑयल 92.58 रुपये था, उसका दाम थोड़ा बढ़ा है और बढ़कर 95.57 रुपये हुआ है। पाम ऑयल का दाम 65.35 रुपये था, वह 68.14 रुपये हुआ है। मस्टर्ड ऑयल के दाम में थोड़ी वृद्धि हुई है, वह 102.92 रुपये था, उसका दाम बढ़कर 108.54 रुपये हुआ है। ग्राउंडनट ऑयल 121.41 रुपये था, जो बढ़कर 136.7 रुपये हुआ है।

महोदय, हमारे यहां पर तेल का प्रोडक्शन केवल 40 प्रतिशत होता है, 60 प्रतिशत तेल का आयात हम दूसरे मुल्कों से करते हैं। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**... उसके बाद चाय का नम्बर आता है, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। चाय का दाम 206.87 रुपये था, अभी लूज टी का दाम 197.98 रुपये है। पैक्ड सॉल्ट का दाम 14.75 रुपये था, जो अभी 14.81 रुपये है। मिल्क का दाम 39.43 रुपये था, जो आज 40.43 रुपये है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः दूध 50 रुपये किलो है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवानः एक मिनट, हम दाल पर ही आ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... गुड़ का दाम 39.94 रुपये था, अब उसका दाम 42.42 रुपये है। चीनी का दाम बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... चीनी का दाम 29.06 रुपये था, जो बढ़ कर 40.15 रुपये हुआ है। इसका कारण यह था कि पूरा का पूरा सदन, खासकर हमारे जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के साथी थे, उनकी बार-बार यह मांग थी कि चीनी मिल बंद नहीं हो, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए। इम्पोर्ट ड्यूटी से लेकर एक्सपोर्ट इन्सेंटिव देने तक, सारी की सारी चीज़ें सरकार के द्वारा की गईं।

इसके बाद अब प्याज का नम्बर आता है। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट। ...**(व्यवधान)**... हम आपकी बात पर भी आएंगे। ...**(व्यवधान)**... देखिए, तीन सीज़नल चीज़ें हैं, प्याज, आलू और टमाटर। प्याज का दाम 29.63 रुपये था, जो आज 16.93 रुपये है। इस सदन में और उस सदन में भी बहुत हल्ला हुआ कि साहब, प्याज सड़ रहा है, सरकार को प्याज खरीदना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शमशेर सिंह ढुलोः पंजाब में ही प्याज 40-50 रुपये किलो मिल रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप कौन सी मंडी का दाम बता रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवानः ...**(व्यवधान)**... दाम बढ़ जाए, तो हल्ला और दाम घट जाए, तो हल्ला। ...**(व्यवधान)**... दोनों हाउसेज़ में हल्ला हुआ कि प्याज कौड़ी के भाव बिक रहा है, सरकार इसको खरीदने का काम करे और हमने 20,000 टन प्याज खरीदने का काम किया।

दाम के बारे में हम बता रहे हैं कि यह सीज़नल चीज़ है, इसलिए ऐसी चीज़ों का दाम बहुत बढ़ भी जाता है और बहुत घट भी जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे एपीएमसी। आज आप पंजाब में चले जाइए या दूसरे राज्यों में चले जाइए, जहां एपीएमसी है, वहां किसान को मंडी को थ्रू आना पड़ता है। एक ही चीज़ होती है, जो किसान के पास से एक भाव में बिकती है, मंडी में दूसरे भाव में बिकती है और बाजार में आने के बाद तीसरे भाव में बिकती है। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, एक मिनट। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Silence please. ...(*Interruptions*)... Order, please. ...(*Interruptions*).. Let the Minister reply, please.

श्री रामविलास पासवानः हमने तो कभी किसी को टोका नहीं है। ...**(व्यवधान)**... एपीएमसी ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। फिर जीएसटी वाला मामला है, लेकिन उससे बहुत सुधार नहीं होगा, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, इसलिए उसको भी हमें करना है। पूरे हाउस को इसे करना है।

इस तरह प्याज के दाम कम हुए, लेकिन टमाटर का दाम थोड़ा बढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... 24.07.2015 को टमाटर का दाम 29 रुपये था, जो आज 39 रुपये है।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः टमाटर 80 रुपये किलो है।

श्री हुसैन दलवईः पूरा देश आपकी बात को सुन रहा है। ...**(व्यवधान)**... आप क्या बोल रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः हुसैन दलवई जी, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... अरे, आप उनको रिप्लाई देने दीजिए।...**(व्यवधान)**... Let him reply. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवानः दलवई जी, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, उसी स्कूल से हम भी पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा शान्ति, शान्ति, शान्ति। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः पहले आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवानः आलू के दाम में थोड़ी वृद्धि हुई है। उसके बाद दाल आती है। मुख्य रूप से यह सारा जो मामला है, यह चर्चा किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, यह चर्चा ज्यादातर सिर्फ दाल के ऊपर है। मैं इस बात को मानता हूँ। यदि आप दाल का देखेंगे, तो एक साल पहले मूंग की दाल 98.20/- रुपए किलो थी, आज मूंग की दाल 95.74/- रुपए है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आप क्या बात कर रहे हैं? डेढ़ सौ रुपए का भाव है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवानः एक मिनट। मसूर की दाल जो है ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Please. ...(*Interruptions*)... He is not yielding. ...(*Interruptions*)... Mr. Rajeev Shukla, he is not yielding. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Sir, he should not mislead the House. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, he should not mislead the House. ...(*Interruptions*)...

श्री राजीव शुक्लः सर, मंत्री जी जिस कागज से पढ़ रहे हैं, मैं निवेदन यह करूंगा कि उस कागज को ऑथेंटिकेट करें और सदन के पटल पर रखें, ताकि बाहर जाकर हम उस प्राइस को मीडिया में भी क्वोट कर सकें। **...(व्यवधान)...** मंत्री जी इसको ऑथेंटिकेट करें कि कौन से डॉक्युमेंट्स हैं, जिनमें यह प्राइस लिस्ट दी हुई है। **...(व्यवधान)...** इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए। बिना ऑथेंटिकेशन के कैसे मानें? **...(व्यवधान)...** किन हाथों ने यह लिखकर दिया, कैसे यह मिला? यह डॉक्युमेंट सदन के पटल पर ऑथेंटिकेट करके रखें। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः कौन से डॉक्युमेंट के लिए बोलना है? **...(व्यवधान)...** What is the document? That is all that you need to say. ...(*Interruptions*)...

श्री राजीव शुक्लः डॉक्युमेंट को ऑथेंटिकेट करें। **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः सुनिए। **...(व्यवधान)...** Now, please sit down. ...(*Interruptions*)... Now, please sit down. Let him complete. ...(*Interruptions*)...

श्री राजीव शुक्लः जो भाव आप बता रहे हैं, अगर बाजार में लेने जाओ, तो जमीन आसमान का अंतर है। **...(व्यवधान)...**

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश)ः आप जगह का नाम बताइए, कहां से यह सामान लें? **...(व्यवधान).....**

†**جناب جاوید علی خان:** آپ جگہ کا نام بتائیے، کہاں سے یہ سامان لیں؟ ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. ...(*Interruptions*)... He is giving the reply. Let him do that. ...(*Interruptions*)...

श्री रामविलास पासवानः उपसभापति जी, अगर यह हल्ला करना है सिर्फ हल्ला करने के लिए, तो कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, मैंने किसी को टोका नहीं। राजा जी बोल रहे थे, मैं उसी समय एफसीआई के संबंध में जवाब देना चाहता था। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के संबंध में सीताराम येचुरी जी बोल रहे थे, मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री उपसभापतिः अब जवाब दे दीजिए। **...(व्यवधान)...** Please continue.

श्री रामविलास पासवानः अब जो ऑथेंटिकेशन का सवाल है, रामविलास पासवान यहां बोल रहे हैं, मीडिया में जा रहा है, आपको लगता है कि गलत बोलते हैं तो प्रिविलेज मोशन लाइए। आप लाइए हमारे खिलाफ, कि ये गलत बोल रहे हैं। **...(व्यवधान)...** सुनिए, यहां रामविलास पासवान नहीं बोल रहा है, भारत सरकार का खाद्य मंत्री बोल रहा है। **...(व्यवधान)...** सर, यह

† Transliteration in Urdu script.

[श्री रामविलास पासवान]
सही है कि जो तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, **...(व्यवधान)...** जैसे अब चने की दाल है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि चने की पैदावार में क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है, प्याज का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, पिछली बार जो 189 लाख टन था वह इस बार बढ़ कर 203 लाख टन हुआ। आलू का जो प्रोडक्शन 480.9 लाख टन था वह इस बार घट कर 455.69 टन हो गया, टमाटर का जो 174 लाख टन था वह इस बार बढ़ कर 181.65 लाख टन हो गया। इसी तरीके से चीनी का जो उत्पादन 284 लाख टन था, इस बार इथनोल वगैरह का प्रयोग हुआ, जो हम लोग भी चाहते थे कि इथनोल वगैरह में जाए, तो 252 लाख टन हुआ। गेहूं का उत्पादन जो 865 लाख टन था, इस बार वह 940 लाख टन हुआ है। चावल का उत्पादन जो 1054.8 लाख टन था, वह इस बार 1033.6 लाख टन हुआ है। हम यह कहना चाहते हैं कि टमाटर में, पोटेटो में, प्याज में पैदावार में कोई कमी नहीं है, लेकिन दाम क्यों बढ़ रहे हैं? उसके दाम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण सप्लाई चेन है और दाम के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जमाखोरी है। **...(व्यवधान)...** अब जमाखोरी के खिलाफ भारत सरकार के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। **...(व्यवधान)...** एक मिनट। अब बार-बार टोका-टोकी कीजिएगा, तो मैं बैठ जाऊंगा। **...(व्यवधान)..**

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): This is not done. ...(*Interruptions*)... This is not done. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please allow him to reply. ...(*Interruptions*)... This is not proper. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, this is not proper. Please allow the Minister to reply. ...(*Interruptions*)... Listen to me. ...(*Interruptions*)... I am on my legs. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*).. Hon. Minister listened to all what you said...(*Interruptions*)... Now, you listen to his reply...(*Interruptions*)... If you have any doubt after that, get the clarification ...(*Interruptions*)... But don't interrupt him like this. ...(*Interruptions*).. Let him reply. ...(*Interruptions*)... Hon. Minister, you please continue. ...(*Interruptions*)..

श्री रामविलास पासवानः सर, मैं आपसे यह कह रहा था कि जो मुख्य मुद्दा है.. अभी इधर से या उधर से हमारे एक साथी ने कहा कि आपने खाद्य मंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलायी? हम पिछली बार भी राज्य के जितने खाद्य मंत्री थे, उनकी बैठक बुलाई और इस बार भी 25.05.2016 को खाद्य मंत्रियों को बुलाया। मैं आज से राजनीति में नहीं हूँ। प्रमोद तिवारी जी से लेकर बहुत से लोग कांग्रेस में हैं, वे जानते हैं कि हम लोग किसी चीज़ को छिपाते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि इस पर जो बहस है, उसका एक सार्थक नतीजा निकले। आप जाकर अपनी-अपनी राज्य सरकार से, खाद्य मंत्री से पूछिए। जो भी अच्छे सुझाव आए हैं, हमने सबको मानने का काम किया है।

सर, बफर स्टॉक की बात की गई। तो 2-3 साल पहले 2014-15 में 171 लाख टन पैदावार हुई, जबकि डिमांड 226 लाख टन हुई। अभी पैदावार 170 लाख टन है, जबकि डिमांड 246 लाख टन हो गई है। मतलब 76 लाख टन का गैप है। भारत सरकार बहुत कम इम्पोर्ट करती है। प्राइवेट वाले इम्पोर्ट करते हैं। **...(व्यवधान)...** आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने पहले 45 लाख टन का इम्पोर्ट किया, दूसरे साल उन्होंने 58 लाख टन का इम्पोर्ट किया, इस बार भी वे

6.00 P.M.

58-60 लाख टन का इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहां 76 लाख टन का गैप है। अब उसके बाद यदि मार्केट में डिमांड और सप्लाई में अन्तर हो जाए, जैसा हमारे साथियों ने कहा कि यदि डिमांड और सप्लाई में अन्तर होगा, तो दाम बढ़ेगा, तो उसके लिए हम लोग भारत सरकार के द्वारा पहली बार बफर स्टॉक बना रहे हैं। वह बफर स्टॉक आज तक कभी नहीं बना था। पहले हमने डेढ़ लाख टन का किया, बाद में वह बढ़ कर 8 लाख टन हुआ और अभी उसे बढ़ा कर 20 लाख टन का किया गया है। इसका उपाय एक ही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन को बढ़ाने के दो ही उपाय हैं— एक तो हम किसान को प्रेरित करें कि वे अधिक से अधिक दाल का उत्पादन करें और दूसरा मौसम है, यानी हमारे यहां मौसम ठीक रहे। 425 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाया गया। पिछली बार यह 275 रुपये बढ़ाया गया। बफर स्टॉक के अलावा, हमने एमएसपी के अलावा दाल पर हमने स्टॉक लिमिट लगा दिया। अब उसमें से दो-तीन राज्य सरकारों को छोड़ कर सारी की सारी सरकारें इसे इम्प्लीमेंट कर रही हैं। एक लाख अड़तीस हजार टन सीज़ किया गया है। ...**(व्यवधान)**... आप नाम लेने को मत कहिए, लेकिन अभी तक एक लाख अड़तीस हजार टन सीज़ किया गया है। हम इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार राज्य सरकार को अनुमित दे सकती है कि आप स्टॉक लिमिट लगाओ। यदि कोई स्टॉक लिमिट से ज्यादा रखता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, छापेमारी करो और जेल भेजने का काम करो। हम तो यह नहीं कर सकते हैं, यह तो राज्य सरकार को करना है।

सर, इम्पोर्टर्स विदेश से आयात करते थे और म्यांमार के पोर्ट पर रख देते थे। जब यहां पर दाम बढ़ता रहता था, तो वे उसे धीरे-धीरे लाने का काम करते थे। अभी हमने कह दिया है, हमने स्टॉक लिमिट लगायी, तो किसी इम्पोर्टर ने कहा कि हम पर स्टॉक लिमिट लगा दोगे, तो हम 10,000 टन से ज्यादा कैसे लाएँगे? तब हमने कहा कि आपको जितना लाना है लाओ, लेकिन वह पोर्ट पर 45 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हमने राज्य सरकार को भी कहा है, वह इसके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई करे। हमारे पास है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह टोटली राज्य सरकार का है ...**(व्यवधान)**...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, it is 6 o' clock now. ...(*Interruptions*)...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am not going to disturb the Minister. मंत्री जी जो बोल रहे हैं, उसको हम सुन रहे हैं। वे और बोलेंगे, उसके बाद हम लोग उनसे clarifications भी पूछेंगे, लेकिन अभी 6 बज गए हैं, क्या आप इसके बाद दूसरा बिल लेने की सोच रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... Are you planning to take up the next Bill?

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh) No Bill ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, one minute. ...(*Interruptions*)... कृपया आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... See, I hope you know that today, at 1.00 p.m., there was a meeting of the leaders convened by the hon. Chairman. In that meeting, which was presided over by the hon. Chairman, in his presence, it was decided that it is not enough that we have only discussions; the Government Business should also be transacted. Therefore, it was decided ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)...

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: We are not going to sit up to 10 o'clock. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you are not ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... I know that the LoP was there. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): The House is supreme. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me complete. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)... That is not the point. See, it is my duty. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): The House is the supreme authority. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know it. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)... I am on my legs. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Every Member has a right to give his opinion. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I agree that you have a right. ...(*Interruptions*)... Please listen to me. ...(*Interruptions*)... Let me complete. ...(*Interruptions*)...

SHRI PALVAI GOVARDHAN REDDY: Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. Are you not seeing that I am standing? Sit down. ...(*Interruptions*)... You are not listening. In that case, it is a failure of the Deputy Chairman. ...(*Interruptions*)... I have to admit this because today, with hon. Chairman presiding over the meeting, it was decided by all the leaders that we would complete this discussion and also we would take up one Bill. ...(*Interruptions*)... Let me complete. It was decided. It was repeatedly asked and it was accepted, including by the Leader of the Opposition. ...(*Interruptions*)... Are you not seeing that I am talking? Then, you come here also. You come here and talk. This is very unfair. Let me say. The House is supreme. You can take any decision, but I have to say what I have to say. I need your indulgence also. It is not that I always hear what you say. You should also hear what I say. Listen or don't listen, obey or don't obey, that is a different matter.

So, it was decided, and when it was told that today, this discussion and the Bill would be taken up, no leader opposed and it was accepted. My understanding is that it was decided. Now, why do I say that it is my failure? If the Bill is not to be taken up, it is my failure. I admit that. The reason is that ...(*Interruptions*)... You listen to me. Why don't you listen to me? If I am talking nonsense, you can

say after listening to me that the Deputy Chairman talked nonsense, but listen to me. The time allotted and decided for the Short Duration Discussion was two-and-a-half hours. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: It has taken four hours now. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying. When it started, I said that the time was two-and-a-half hours. ...(*Interruptions*)... What has happened to you? ...(*Interruptions*)... सुनिए...**(व्यवधान)...** Let me say. I said that it was two-and-a-half hours. I asked hon. Members to adhere to the time. Then, a suggestion came from this side and that side that the subject is very important; don't be very strict. Therefore, I was also liberal, the Vice-Chairman sitting here was also liberal, and, that is why, it has come up to 6 o' clock. Had the Chair been strict, it would have been over by 4 'o clock or by 4.30 p.m., and, we would have taken up the Bill. Therefore, if the Bill is not taken up today — it would be on record — it would be a failure on the part of the Deputy Chairman. You do what you want. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY (Odisha): I support you, Sir. ...(*Interruptions*)... I can't see you as a failure. ...(*Interruptions*)... Let us take up the Bill. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, please. ...(*Interruptions*)... It is unfair. ...(*Interruptions*)... Now, let the Minister anyway complete the reply. ...(*Interruptions*)... We are extending the time. ...(*Interruptions*)... Let the Minister complete the reply. ...(*Interruptions*)...

श्री रामविलास पासवानः महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने कई कदम उठाए हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम चाह भी रहे हैं कि जो भी माननीय सदस्य का सुझाव आएगा, हम करेंगे। लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने हर राज्य सरकार से कहा है। अब हमारे साथी ने कहा है कि विदेश से खराब दाल आ रही है। दलवई जी ने कहा कि उसको यहां लोग खाते नहीं हैं। विदेश में जो प्रोडक्शन है, वहां लोग दाल बहुत कम खाते हैं, यहां भी लोग दाल बहुत कम खाते हैं। पश्चिमी बंगाल में लोग बहुत ही कम दाल खाते हैं, वहां मछली ज्यादा खाते हैं। विदेशों के लिए दालों का सबसे ज्यादा उपभोक्ता भारत में है। आप कहीं देखेंगे 2012 में जो वर्ल्ड प्रोडक्शन of pulses है, जो आई.सी.ए.आर. के अनुसार है, वह 75 मिलियन टन था, जो घट करके 2013 में 73 हो गया और अब घट करके 71 हो गया है। हमारे साथी ने कहा कि विदेशों से दाल किस रेट में मंगाते हो? हमारे साथी श्री सीताराम येचुरी ने पूछा था। हम तुअर दाल 76 रुपए से लेकर के 99 रुपए प्रति किलो तक मंगाते हैं। जो हमारा यहां लैंडिंग प्राइस है, उड़द की दाल 78 रुपए से लेकर के 109 रुपए प्रति किलो तक मंगाते हैं। बस हम खत्म कर रहे हैं।

हम इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को हम सब्सिडाइज्ड रेट पर 66 रुपए में तुअर दाल दे रहे हैं और उड़द की दाल 82 रुपए में दे रहे हैं। मेरा यह चैलेंज़ है कि जो

[श्री रामविलास पासवान]

भी राज्य सरकार जितना चाहे हम देने को तैयार हैं। हमारे पास पूरी लिस्ट है कि किस राज्य सरकार ने कितना मांगा है और हमने उनको कितना दिया है। मूल्य वृद्धि रोकने के लिए भारत सरकार की ही जवाबदेही नहीं है, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को भी लेनी पड़ेगी। यदि हम राज्य सरकार को 66 रुपए प्रति किलो तुअर दाल दे रहे हैं, अरहर की दाल दे रहे हैं तथा 82 रुपए प्रति किलो हम उड़द की दाल दे रहे हैं, तो क्यों नहीं राज्य सरकार खरीदती है? आपने कहा कि पी.डी.एस. में बांटो। आपको मालूम है कि पी.डी.एस. में 81 करोड़ लाभार्थी हैं। अगर 81 करोड़ लाभार्थियों को एक-एक किलो भी देना शुरु कर दीजिएगा तो कहां आपके पास उतनी दाल है? बहुत राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में कर रही हैं। राज्य सरकारों को करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... सुनिए। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, जो हमारे डी. राजा जी ने कहा, ऐसा यूपीए की सरकार ने 2013 में लागू किया था। उस समय यह 11 राज्यों में था, हम 34 राज्यों में कर चुके हैं। केरल और तमिलनाडु में नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में जो पुलिस मॉडल है सीज़ करने का, वह बहुत अच्छा है। हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितना देते हैं? तीन साल हो गए हैं फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू हुए। दो रुपए किलो गेहूं, तीन रुपए किलो चावल, एक रुपए किलो मोटा अनाज देते हैं। हम बाजार से 30 रुपए, 32 रुपए में चावल खरीदते हैं और हम 81 करोड़ गरीबों को तीन रुपए प्रति किलो चावल गेहूं देते हैं। हम 20 रुपए प्रति किलो में गेहूं खरीदते हैं लेकिन लोगों को दो रुपए में देते हैं। यदि भारत सरकार 30 रुपए में खरीद करके तीन रुपए में चावल दे सकती है तो राज्य सरकार तीन रुपए क्यों नहीं दे सकती है?

जब हम 20 रुपये में से 18 रुपये गेहूं पर दे सकते हैं, तो राज्य सरकार दो रुपये क्यों नहीं दे सकती है? सब चीज़ें आकर केंद्र सरकार पर रुक जाती हैं। आप भी केंद्र सरकार में रहे हैं, हम भी रहे हैं। हम लोग दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, दो रुपये किलो गेहूँ, तीन रुपये किलो चावल दे रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें हैं, जो अपनी पॉकेट से कुछ देती हैं, वे एक रुपया, दो रुपया कमीशन देने का काम करती हैं। उपसभापति जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दाल की कीमत जब इतनी बढ़ रही है, तो राज्य सरकारें टैक्स क्यों नहीं माफ कर देती हैं? दाल के ऊपर से वे वैट को क्यों नहीं खत्म कर देती हैं? उनसे किसने कहा है कि आप इम्पोर्ट मत कीजिए, उनसे किसने कहा है कि आप छापेमारी मत कीजिए, उनसे किसने कहा है कि आप जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए? इसलिए उपसभापति महोदय, मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि हमारा जो भी है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात): गुजरात में आपकी सरकार है, तो वहां आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ...**(व्यवधान)**... गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कार्रवाई करने से आपको कौन रोक रहा है? ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: एक मिनट ...**(व्यवधान)**...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: जहां आपकी सरकार है, वहां आपको किसने रोका है? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All of you sit down. ..(*Interruptions*).. Please. ...(*Interruptions*)...

श्री मधुसूदन मिस्त्री: बड़े-बड़े व्यापारी लोग ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister complete the reply. ...(*Interruptions*)...

श्री मधुसूदन मिस्त्रीः भारत सरकार अपने आपको राज्य सरकारों से अलग नहीं कर सकती है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistryji, let him complete the reply. ...(*Interruptions*)...

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश)ः आप और आपकी सरकार जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

†جناب محمد علی خان: آپ اور آپ کی سرکار ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے ---(مداخلت)---

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(*Interruptions*)... Let him complete the reply. ...(*Interruptions*)...

श्री रामविलास पासवानः सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि दाल के सिवाय किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ी है। **...(व्यवधान)...** दूसरी चीज़ यह है कि हम यह घोषणा करते हैं कि तूअर की दाल 66 रुपये किलो और उड़द की दाल 82 रुपये किलो। जो भी सरकार चाहे वह न खरीदे वह जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। उस कार्रवाई का नतीजा दो टर्म है, एक लांग टर्म प्रोग्राम है जो म्यांमार से लेकर मोजाम्बिक तक है। मोजाम्बिक में प्रधान मंत्री जी गए और वहां एमओयू साइन हुआ, उसके बाद दो साल के अंदर दाल की कीमत इतनी कम हो जाएगी कि हल्ला होने लगेगा कि दाल की कीमत बढ़ाइए। सर, अभी जनवरी में दाल की कीमत 43 परसेंट थी, जो फरवरी में घटकर 38 परसेंट हुई, फिर मार्च में वह 34 परसेंट हो गई, अप्रैल में 34 परसेंट हुई, मई में 31 परसेंट हुई है और अब जून में आकर वह 26.9 प्रतिशत बचा है और इस पर हम कब्जा करेंगे, लेकिन हम राज्य सरकारों से भी आग्रह करेंगे कि वे केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करके लोगों को सस्ती दर पर दाल बेचने का काम करे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद)ः सर, ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि दाल के सिवाय किसी चीज के दाम नहीं बढ़े हैं। **...(व्यवधान)...** आपके खिलाफ प्रिविलेज़ हो जाएगा। दूध, सब्जी, अंडा, गोश्त से लेकर हिन्दुस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जिसके दाम न बढ़े हैं और आप यह कह रहे हैं कि दाल के अलावा किसी और चीज के दाम नहीं बढ़े हैं! आप यह क्या बता रहे हैं? **...(व्यवधान)...**

†قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد): سر، آنریبل منسٹر نے کہا کہ دال کے سوائے کسی چیز کےدام نہیں بڑھے ہیں ---(مداخلت)--- آپ کے خلاف پریولیج ہو جائے گا۔ دودھ، سبزی، انڈا، گوشت سے لیکر ہندوستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جس کے دام نہ بڑھے ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال کے علاوہ کسی اور چیز کے دام نہیں بڑھے ہیں۔ آپ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ---(مداخلت)---

† Transliteration in Urdu script.

श्री रामविलास पासवानः मैं आपको बताऊँ ?

श्री गुलाम नबी आज़ादः हां, बताइए। ...**(व्यवधान)**... आप यह बताइए कि आप इसका समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यह राज्यों को करना चाहिए या वे नहीं करें, लेकिन यह कहना उचित नहीं है कि दाल के अलावा किसी और चीज़ के दाम नहीं बढ़े हैं। आज हर चीज़ के दाम बढ़े हैं। ...**(व्यवधान)**... यह मैं आपके हित के लिए कह रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب غلام نبی آزاد:** ہاں، بتائیے ---(مداخلت)--- آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کا سمادھان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ راجیوں کو کرنا چاہئے یا وہ نہیں کریں، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ دال علاوہ کسی اور چیز کے دام نہیں بڑھے ہیں- آج ہر چیز کے دام بڑھے ہیں ---(مداخلت)--- یہ میں آپ کے ہت کے لئے کہہ رہا ہوں ---(مداخلت)---

श्री रामविलास पासवानः आप लीडर ऑफ दि अपोज़िशन हैं। ...**(व्यवधान)**... यदि किसी चीज़ का दाम 29 रुपये था और आज वह बढ़कर 32 रुपये हो गया है, तो बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, तो साल-दो साल में कुछ पैसे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ादः सर, ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाब से हम बिल्कुल असंतुष्ट हैं and we are walking out.

†جناب غلام نبی آزاد: سر، آنریبل منسٹر کے جواب سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں and we are walking out.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have a clarification since I initiated this discussion. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to take up the Bill. What is your point? ...*(Interruptions)*... Let me take up the Bill. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, we have come here in Parliament to raise issues. ...*(Interruptions)*... I have got a serious question. अपने बयान के समय मैंने प्रेजेंट किया, I laid two papers on the Table of the House certified as per Rule 39(3) the prices from 30 different markets in 17 States in respect of *dal*. What I certified and placed on the Table of the House does not seem to match with the figures given by the Minister. So, my point is, I placed this with all responsibility. Sir, through you, I beg the Minister to look into this because we have made this the benchmark to see that these prices come down. So, these prices, which we got from the markets, and his numbers are not matching.

† Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... अभी बिल लेना है। **...(व्यवधान)...**

श्री जावेद अली खान: माननीय उपसभापति महोदय, मैं मंत्री जी के reply के ऊपर बात कर रहा हूं। उसके सबंध में मैं अपना clarification पूछ रहा हूं।

†جناب جاوید علی خان: مانیئے اُپ سبھاپتی مہودے، میں منتری جی کے ریپلائی کے اوپر بات کررہا ہوں۔ اس کے سمبندھ میں میں اپنا کلیری فکیشن پوچھ رہا ہوں۔

श्री उपसभापति: अभी बिल लेना है।

श्री जावेद अली खान: बिल लेना है, लेकिन clarification पूछने का हमारा भी राइट है, केवल अगली लाइन से ही clarification पूछे जाएंगे, पीछे वालों को पूछने दीजिए।

†جناب جاوید علی خان: بل لینا ہے، لیکن کلیری فکیشن پوچھنے کا ہمارا بھی رائٹ ہے، صرف اگلی لائن سے ہی کلیری فکیشن پوچھے جائیں گے، پوچھے والوں کو پوچھنے دیجئے۔

श्री उपसभापति: आप पूछिए। बिल लेना है, लेकिन पूछिए।

श्री जावेद अली खान: मैं यह बात जानता हूं कि अपनी विफलता को, अपनी असफलता को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे, उस वक्त भी मैं पूछ रहा था और उससे पहले जो वक्ता उनके समर्थन में बोल रहे थे, उस समय भी मैं पूछ रहा था। मंत्री जी ने खुद बताया कि दाम तीन होते हैं, खेत का दाम अलग है, मंडी का दाम अलग है और बाज़ार का दाम अलग है। यहां मंत्री जी जो दाम quote कर रहे थे, मैंने कहा कि मुझे उसका पता बता दें कि कहां इस दाम पर सामान मिल रहा है, मैं अपने घर का सामान वहीं से खरीदना शुरू कर दूंगा। वे बता नहीं रहे हैं। **...(व्यवधान)...** प्लीज़, मुझे बताया जाए कि 60 रुपए में दाल कहां मिल रही है और 70 रुपए में तेल कहां मिलता है? मैं वहीं से अपने घर का सामान खरीदना शुरू कर दूंगा।

†جناب جاوید علی خان: میں یہ بات جانتا ہوں کہ اپنی وِ یفلتا کو اپنی اَسفلتا کو سُویکار کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب منتری جی جواب دے رہے تھے، اس وقت بھی میں پوچھ رہا تھا اور اس سے پہلے جو وَکتا ان کے سمرتھن میں بول رہے تھے، اس وقت بھی میں پوچھ رہا تھا۔ منتری جی نے خود بتایا کہ دام تین ہوتے ہیں، کھیت کا دام الگ ہے، منڈی کا دام الگ ہے اور بازار کا دام الگ ہے۔ یہاں منتری جی جو دام کیوٹ کررہے تھے، میں نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتادیں کہ کہاں اس دام پر سامان مل رہا ہے، میں اپنے گھر کا سامان وہیں سے خریدنا شروع کر دونگا۔ وہ بتا نہیں رہے ہیں۔۔۔(مداخلت)۔۔۔ پلیز، مجھے بتایا جائے کہ ساٹھ روپے میں دال کہاں مل رہی ہے اور ستّر روپے میں تیل کہاں ملتا ہے؟ میں وہیں سے اپنے گھر کا سامان خریدنا شروع کردونگا۔

† Transliteration in Urdu script.

श्री रामविलास पासवानः मैं बता रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... यहां पर हमारे बिहार के साथी हैं। मैं आज से एक सप्ताह पहले मैं अपनी constituency हाजीपुर में गया हुआ था। आप नोट कर लीजिए, हाजीपुर में महनार एक प्रखंड है, महनार प्रखंड में चमरहारा एक गांव है। जब मैं वहां गया, हमारा बिहार डीसीपी स्टेट है, वहां एफसीआई नहीं खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है। वहां के किसान आए, उन्होंने मेरा घेराव किया कि हम अरहर की दाल एमएसपी रेट पर बेचना चाहते हैं, यहां सरकार नहीं खरीद रही है। हमने पूछा कि आपके पास कितनी दाल है तो एक आदमी ने कहा कि मेरे पास 4 क्विंटल है। उसका नाम था, कौशल किशोर सिंह। हमने वहीं से टेलीफोन किया, श्री हेम पांडे हमारे कंज्यूमर के सेक्रेटरी हैं। हमने उनसे कहा कि राज्य सरकार दाल नहीं खरीद रही है, बाज़ार में दाल की किल्लत है, आप तुरंत खरीदिए। ...**(व्यवधान)**... आप सुनिए। तीसरे दिन भारत सरकार के द्वारा दाल को खरीदने का काम किया गया। आपकी सरकार की जवाबदेही है या नहीं? इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। ..**(व्यवधान)**..

श्री जावेद अली खानः तो क्या हम दाल खरीदने के लिए हाजीपुर जाएं? ...**(व्यवधान)**... तब तो दाल यहां से भी महंगी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**...

†**جناب جاوید علی خان:** تو کیا ہم دال خریدنے کے لیے حاجی پور جائیں؟ ---(مداخلت)--- تب تو دال یہاں سے بھی مہنگی پڑیگی---(مداخلت)---

श्री रामविलास पासवानः हम अपने क्षेत्र हाजीपुर में गए, वहां देखा। आप अपने क्षेत्र में जाकर देखिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up further consideration of the Motion moved by Shri Anil Madhav Dave. He has already moved the Bill. ...(*Interruptions*)... I am taking up the discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, at 6 o'clock, I had said that the House will continue till the hon. Minister completes his reply. My submission is, let the first speaker speak and after that, we will take it up tomorrow. So, we can go up to 6.30 p.m. I think that was the consensus. We can take it up to 6.30 p.m. ...(*Interruptions*)... अगर हम कहते कि कल ही लें तो आपको शक होगा कि बिल नहीं ले रहे। हम आपको रास्ता दे रहे हैं।

†اگر ہم کہتے ہیں کہ کل ہی لیں تو آپ کو شک ہوگا کہ بل نہیں لے رہے۔ ہم آپ کو راستہ دے رہے ہیں۔

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): आप दिन में बहुत reasonable होते हैं, लेकिन शाम होते-होते थोड़ा unreasonable हो जाते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ादः अगर हम कहें कि कल लें तो आप कहेंगे, बिल को रोकने के लिए कह रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक स्पीकर बोल ले, तो बिल तो नहीं रुक रहा।

†**جناب غلام نبی ازاد:** اگر ہم کہیں کہ کل لیں تو اپ کہیں گے، بل کو روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسپیکر بول لے، تو بل تو نہیں رُک رہا۔

† Transliteration in Urdu script.

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः सर, बहुत ज्यादा स्पीकर्स नहीं हैं। फर्स्ट स्पीकर जयराम रमेश जी हैं। वही मुख्य स्पीकर हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ादः आपकी शंका को दूर करने के लिए हमने दस मिनट का कहा, वरना हम कल का ही कहते। **...(व्यवधान)...**

†جناب غلام نبی ازاد: اپ کی شنکا کو دور کرنے کے لیے ہم نے دس منٹ کا کہا، ورنا ہم کل کا ہی کہتے---(مداخلت)---

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः इसमें जयराम रमेश जी मुख्य स्पीकर हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि सात, साढ़े सात बजे तक यह समाप्त हो जाएगा।

श्री नीरज शेखरः क्या कांग्रेस और भाजपा में कुछ सहमति हो गयी है? क्या आप में बिल को लेकर सहमति हो गयी है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, all right. ...(*Interruptions*)... Up to 7.00 p.m., okay? ...(*Interruptions*)... Ghulam Nabiji, up to 7.00 p.m.? ...(*Interruptions*)... Shri Jairam Ramesh, please start. ...(*Interruptions*)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if it is up to 6.30 p.m., I am not going to speak. ...(*Interruptions*)... If it is up to 7.00 p.m., I will speak. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, let him speak. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct. ...(*Interruptions*)... So, let us have a compromise, 7.00 p.m. is okay. ...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Sir, let him finish. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: What is this, Sir? ...(*Interruptions*)... Are we not in the House? ...(*Interruptions*)... Are only the BJP and the Congress in the House? ...(*Interruptions*)... Will they both decide 6 o' clock or 7 o' clock? ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, please allow me for a minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: I am protesting, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do not get. ...(*Interruptions*)... नाराज मत होइए। **...(व्यवधान)...** नाराज मत होइए। **...(व्यवधान)...** Kindly note, tomorrow there is a Short Duration Discussion on a subject which is very important, that is relating to Andhra Pradesh. Therefore, tomorrow also, we will have problem of time. So, let us sit up to 7.00 p.m. and have one or two speakers so that.....(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, please allow me to speak. ...(*Interruptions*)...

† Transliteration in Urdu script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... It will be 7.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, just a minute. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to say? ...(*Interruptions*)... 7.00 p.m. ...(*Interruptions*)...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः सर, हमारी रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल जयराम रमेश जी जितनी देर बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलने दीजिए। ये फर्स्ट स्पीकर हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वे जितनी देर बोलना चाहते हैं, आप उनको बोलने दीजिए। उसके बाद अगर समय मिलेगा, तो दूसरे ऑनरेबल मेम्बर्स बोल लेंगे। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, Mr. Jairam Ramesh will start. ...(*Interruptions*)... In any case,.....(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Just a minute, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. ...(*Interruptions*)... Please start. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, please allow me for a minute. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... I have called Mr. Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... I am not allowing anybody else. ...(*Interruptions*)... Mr. Jairam Ramesh can start. ...(*Interruptions*)... Yes. ...(*Interruptions*)... I am not allowing. ...(*Interruptions*)... Your time is over. ...(*Interruptions*)... Shri Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)... I cannot listen to everybody and take a decision. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Not allowed. ...(*Interruptions*)... Mr. Jairam Ramesh to start. ...(*Interruptions*)... Not allowed; Mr. Jairam Ramesh to start. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, why only left and right? Why not middle? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. ...(*Interruptions*)... Mr. Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: So, do we come to the House tomorrow or not? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(*Interruptions*)... Do not talk anything like this. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Then, please allow me. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I have already given. ...(*Interruptions*)... I am

not allowing it. No. ...(*Interruptions*)... I called him. ...(*Interruptions*)... I am not allowing you; sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, just tell me when the Indian Medical Council Bill is going to come up because every day I am coming with my preparation. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is good. ...(*Interruptions*)... You should come every day. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: I will come. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...(*Interruptions*)... It is your duty to come every day. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Shri Jairam Ramesh. ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... It is not going on record....(*Interruptions*)... Mr. Jairam Ramesh, please. ...(*Interruptions*)... Whatever you said will not go on record. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... What is your problem? ...(*Interruptions*)... आपकी प्रॉब्लम क्या है? **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखरः सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कांग्रेस के सदस्य और बीजेपी के सदस्य ही सदन का समय तय करेंगे? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः ऐसा नहीं। **...(व्यवधान)...** ऐसा नहीं। **...(व्यवधान)...**

श्री अनुभव मोहंतीः सर, ऐसा ही हो रहा है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not allowed you. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)... I will name you. ...(*Interruptions*)... You sit down. ...(*Interruptions*)... I will name you. ...(*Interruptions*)... Listen, all Leaders, including your own Leader,.....(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: No. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Listen, all Leaders decided to sit and discuss the Bill. That is what I am saying. I have not taken this view or that view. I have only conveyed what has been decided and, therefore, I am proceeding. ...(*Interruptions*)... I said, ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: Sir, I am saying, let us take up the whole Bill then. ...(*Interruptions*)... Why only one speaker? ...(*Interruptions*)...

---

*Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Oh, you want more speakers! ...(*Interruptions*)... I am very happy. ...(*Interruptions*)... I have no problem. ...(*Interruptions*)... You have a point. ...(*Interruptions*)... Yours is a valid point. ...(*Interruptions*)...

SHRI NEERAJ SHEKHAR: They have decided that only one speaker will speak. ...(*Interruptions*)... They have decided, till 6.30 p.m. ...(*Interruptions*)... Somebody will decide 7 o' clock. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I agree. ...(*Interruptions*)... Yours is a valid point. ...(*Interruptions*)... आपने ठीक बोला। **...(व्यवधान)...** Why only Mr. Jairam Ramesh? Others should also speak. ...(*Interruptions*)... ठीक है। **...(व्यवधान)...** अनुभव मोहंती, आपकी क्या प्रॉब्लम है? **...(व्यवधान)...**

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, that is what I was saying that when we have decided that we are going to speak on a Bill, when we are going to take up the Bill, then, why all of a sudden, this side or that side decides that after one speaker, there will not be any discussion today. And it will be taken up tomorrow. ...(*Interruptions*)....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please...(*Interruptions*)... Okay...(*Interruptions*)...

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Continue till 10 o' clock or up to 11 o' clock ...(*Interruptions*)...

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Then, why both of you are stopping? ...(*Interruptions*)...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी: हम तैयार हैं, आप 10 बजे तक discussion करिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Anubhav Mohanty, sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Shri Jairam Ramesh to start the speech on the Bill.

GOVERNMENT BILL

The Compensatory Afforestation Fund Bill, 2016 — *Contd.**

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority Bill. The Bill has finally come up for consideration and passage. Before I get into the Bill, I would like to congratulate the new Minister, who has just taken over, and within days of his taking over, he is piloting a very important Bill, which has very

* Further discussion continued from 19th July 2016.